भारी बारिश और खडकवासला बांध से 40,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण पुणे में बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटे में हालात और खराब हो सकते हैं।

जनहितैषी

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 64278/96 वर्ष:29 अंक: 83 दिनांक:26-07-2024 शुक्रवार मूल्य : 1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 वडोदरा M

कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार घोषित एमएसपी पर किसानों से पर्याप्त मात्रा में फसलों की खरीद नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया, वे एमएसपी की घोषणा करते हैं, लेकिन एमएसपी पर खरीद नहीं करते हैं।

पुणे में रातभर हुई झमाझम बारिश से जिले के बड़े हिस्से बाढ़ के पानी में डूबे

पुणे (ईएमएस)। महाराष्ट्र के पुणे में रातभर हुई झमाझम बारिश से जिले के बड़े हिस्से बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। लोगों की मदद के लिए नावों को तैनात किया गया है। वहीं बारिश के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शहर की अग्निशमन ब्रिगेड, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तथा अन्य एजेंसियां कई क्षेत्रों में पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए पहुंच गई हैं। गुरुवार सुबह लोग जब उठे तो उन्होंने खुद को 3-5 फीट गहरे पानी में फंसा पाया। टीमें नावों के माध्यम से फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं।

बचावकर्मियों ने अपने घरों या दुकानों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए नावों और रस्सियों का इस्तेमाल किया, जबकि कुछ घरों में पानी छत तक पहुंच गया है। एनडीआरएफ ने निंबज नगर, डेक्कन जिमखाना और सिंहगढ़ रोड इलाकों में बचाव अभियान शुरू किया है। ये इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। शहर में पिछले 24 घंटों में 200 मिमी से अधिक बारिश हुई है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री तथा पुणे के सांसद मुरलीधर मोहोल ने कहा कि खडकवासला बांध से 40 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने से स्थिति और खराब हो गई है।

नाराज स्थानीय लोगों ने सरकार की आलोचना की है। उनका कहना है कि सरकार ने बिना कोई सूचना के सुबह करीब 4 बजे मुला-मुथा नदी बेसिन में बांध के गेट खोल दिए। यदि उन्हें पहले जानकारी दी जाती तो लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सकते थे।

लगभग पूरे शहर में सड़कें, गलियां और रास्ते बाढ़ के पानी में फंसे दोपहिया और चार पहिया वाहनों से अटे पड़े थे। लोग कमर से गर्दन तक गहरे पानी में घुसकर अपने सामान को बचाने का प्रयास कर रहे थे।

भिड़े ब्रिज, होल्कर ब्रिज, संगम ब्रिज और आसपास की कॉलोनी, गरवारे कॉलेज के पास खिल्लारे कॉम्प्लेक्स, पीएमसी कार्यालय के सामने स्थित पुल जैसे प्रमुख मार्ग यातायात के लिए बंद कर दिए गए हैं। नदियां उफान पर हैं।

खंडाला-लोनावला, पिंपरी-चिंचवाड़, मुलशी, खेड़, भोर, मावल, हवेली, बारामती और अन्य स्थानों के साथ-साथ लवासा शहर में पिछले 24 घंटों में 300 मिमी से ज्यादा भारी बारिश हुई है। पुणे शहर और अन्य कस्बों के कई इलाकों में बचाव एजेंसियों और पुलिस ने लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है।

मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट, पुलिस की लोगों से अपील- घर से बाहर ना निकलें

भारी बारिश को को देखते हुए मुंबई पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। मुंबई पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया कि आईएमडी ने कल सुबह 8.30 बजे तक मुंबई के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। सभी मुंबईवासियों से अनुरोध है कि जब तक आवश्यक न हो घर के अंदर ही रहें। कृपया सुरक्षित रहें।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी वर्षा ने महानगर का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। इसका असर लोकल ट्रेनों पर भी देखा जा रहा है। समुद्र में ज्वार के दौरान हुई भारी वर्षा से महानगर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। रेल की पटरियों पर भी पानी भर जाने से लोकल ट्रेनें भी विलंब से चल रही हैं। वहीं, आईएमडी ने कल सुबह 8.30 बजे तक मुंबई के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है।

भारी बारिश को को देखते हुए मुंबई पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। मुंबई पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया कि आईएमडी ने कल सुबह 8.30 बजे तक मुंबई के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। सभी मुंबईवासियों से अनुरोध है कि जब तक आवश्यक न हो, घर के अंदर ही रहें। कृपया सुरक्षित रहें। किसी भी आपात स्थिति के लिए डायल 100 या डायल 112 करें।

भारी वर्षा के पूर्वानुमान के बीच किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की कई टीमों को तैनात किया गया है, क्योंकि मौसम विभाग (आइएमडी) ने शहर और उपनगरों में भारी वर्षा तथा अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा के लिए अलर्ट जारी किया है।

नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की नौंवी बैठक शनिवार को, जनता से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा; नदारद रहेगा विपक्ष

नई दिल्ली। नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पीने का पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और जमीन व संपत्ति जैसे आम जनता के रोजमर्रा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष शासित राज्य इसका हिस्सा नहीं होंगे। आम जनता के जीवन को सरल बनाने के लिए इन मुद्दों को मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में चिह्नित किया गया था, जिसका विस्तृत रोडमैप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षता में 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में तय किया जाएगा।

2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आम आदमी के जीवन के सुगम बनाने के लिए होने वाली नीति आयोग की इस शीर्ष बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसमें हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। राजधानी दिल्ली में 27 जुलाई शनिवार को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की नौंवी बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बीच कई विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। जाहिर है विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री इन मुद्दों पर अपने-अपने राज्यों में आम जनता से जुड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अहम सुझाव देने से वंचित रह जाएंगे।

कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, पंजाब जैसे विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान कर दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। पहले ममता के बैठक में शामिल होने की खबरें थी, लेकिन माना जा रहा है कि उन पर दबाव है।

नीति आयोग के अनुसार भारत जल्द ही पांच ट्रिलियन जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह है और 2047 तक इसे 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित प्रयास की जरूरत होगी। ध्यान देने की बात है कि नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग कौंसिल की बैठक की तैयारी काफी पहले शुरू हो गई थी। इसके लिए पिछले साल दिसंबर में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक हुई थी। राजधानी दिल्ली में 27 जुलाई शनिवार को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की नौंवी बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में आम जनता के रोजमर्रा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जानी है। इस बीच कई विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इसमें कर्नाटक तमिलनाडु केरल तेलंगाना पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं।

रुपया सर्वकालिक निम्न स्तर 83.72 डॉलर पर

मुंबई (ईएमएस)। विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और विदेशी पूंजी की भारी निकासी के बीच रुपया गुरुवार को कमजोर रुख के साथ खुला और 83.72 प्रति डॉलर के अपने सर्वकालिक निम्न स्तर पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि घरेलू मुद्रा में गिरावट भारतीय शेयर बाजारों में भारी गिरावट के बाद आई है। सरकार के पूंजीगत लाभ पर कर की दर बढ़ाने के फैसले के बाद से घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट जारी है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। वह एक पैसे की गिरावट के साथ अपने सर्वकालिक निचले स्तर 83.72 प्रति डॉलर पर खुला था। रुपया बुधवार को अपने सर्वकालिक निचले स्तर 83.71 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को परखने वाला डॉलर सूचकांक 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 104.21 पर रहा।

सोने का भाव गिरकर 67,900, चांदी 81,500 रुपए के करीब

नई दिल्ली (ईएमएस)। सोने और चांदी के वायदा भाव में गुरुवार को बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोनों के वायदा भाव गिरावट के साथ खुले। सोने के वायदा भाव 67,900 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 81,500 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। वै?श्विक बाजार में भी सोने व चांदी के वायदा भाव में नरमी देखी जा रही है। सोने के वायदा भाव की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अगस्त कॉन्ट्रेक्ट 937 रुपये की गिरावट के साथ 68,015 रुपये के भाव पर खुला। इस समय यह 1,058 रुपये की गिरावट के साथ 67,894 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत सुस्त रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क सितंबर कॉन्ट्रेक्ट 393 रुपये की गिरावट के साथ 84,501 रुपये पर खुला। इस समय यह 3,390 रुपये की गिरावट के साथ 81,504 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। वै?श्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई। कॉमेक्स पर सोना 2,398.10 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 2,415.70 डॉलर प्रति औंस था। इस समय यह 44.50 डॉलर की गिरावट के साथ 2,371.20 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 29.07 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव 29.31 था। इस समय यह 1.24 डॉलर की गिरावट के साथ 28.07 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

खनिजों पर टैक्स के मामले में एण का ऐतिहासिक फैसला, बंगाल, झारखंड और एमपी समेत 6 राज्यों को होगा फायदा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने खदान, खनिज संपन्न राज्यों को भारी राजस्व के प्रोत्साहन वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आठ-एक के बहुमत से दिये फैसले में कहा है कि राज्यों को खदानों और खनिज वाली भूमि व खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है। राज्यों के पास ऐसा करने की विधायी क्षमता और शक्ति है।

शीर्ष अदालत ने खनिज, खदानों के मामले में कर व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव वाले फैसल में कहा है कि रॉयल्टी को कर नहीं माना जा सकता। इस फैसले से खनिज, खदान संपन्न राज्य ओडीशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को फायदा होगा। हालांकि फैसले को पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा या फैसले की तारीख से लागू माना जाएगा इस पर कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने स्वयं और सात अन्य न्यायाधीशों की ओर से बहुमत का फैसला पढ़ते हुए कहा कि रॉयल्टी कर की प्रकृति में नहीं आती क्योंकि यह खनन पट्टे के लिए पट्टेदार द्वारा भुगतान किया गया एक संविदात्मक प्रतिफल है। यानी खनन का पट्टा या ठेका लेने के बदले दिया जाने वाला भुगतान होता है। कोर्ट ने कहा कि रॉयल्टी और डेड रेंट (खनिज भूमि की तय न्यूनतम राशि जिसका भुगतान खनन पट्टा लेने वाला सरकार या भूस्वामी को करता है) दोनों ही टैक्स की विशेषताओं को पूरा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिये बहुमत के फैसले में 1989 के इंडिया सीमेंट मामले में रायल्टी को टैक्स मानने की व्यवस्था देने वाले फैसले को खारिज कर दिया है। बहुमत के इस फैसले को अगर बहुत साधारण शब्दों में समझा जाए तो अर्थ निकलता है कि राज्यों को खनिज अधिकारों और खदानों की भूमि पर कर लगाने का अधिकार है। खदान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) कानून 1957 की धारा 9 के तहत लगने वाली रॉयल्टी टैक्स नहीं है

आधार एनरोलमेंट आईडी से नहीं मिलेगा पैन

नई दिल्ली (ईएमएस)। अक्टूबर से पैन एप्लिकेशन या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार का एप्लिकेशन नंबर मान्य नहीं होगा। इसके लिए अब आधार नंबर ही देना होगा। सरकार ने कहा है कि आधार एप्लिकेशन फॉर्म की एनरोलमेंट आईडी के आधार पर एक से ज्यादा पैन जनरेट हो सकता है, इससे पैन का दुरुपयोग हो सकता है। केंद्र सरकार ने इस ऑप्शन को 1 अक्टूबर 2024 से बंद करने का फैसला किया है। यह सुविधा 2017 से है। लेकिन सरकार का मानना है कि आधार नंबर का कवरेज बढ़ रहा है, और यह भारत के लगभग सभी लोगों को मिल चुका है।

अधिकारियों के खिलाफ पक्के सबूत लेकर लाओ....एक्शन होगा

योगी ने अपने विधायकों से कहा

लखनऊ (ईएमएस)। लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बाद से सीएम योगी एक्शन में दिख रहे है। लगातार बैठकें कर पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम योगी जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में योगी ने अलग-अलग मंडल के विधायकों से मुलाकात करने का सिलसिला शुरू किया है। गुरुवार को सीएम योगी मेरठ मंडल के विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी प्रयागराज मंडल के विधायकों से बात करने वाले है। इसके पहले उन्होंने बरेली मंडल के विधायकों के साथ बैठक की थी। बैठक में विधायकों ने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जमकर शिकायत की है। बैठक में योगी ने कहा था कि किसी भी जनप्रतिनिधि की जीत में 50 प्रतिशत पार्टी की, 50 प्रतिशत भूमिका प्रत्याशी की होती है।

वहीं विधायकों द्वारा अधिकारियों के न सुनने की शिकायत पर योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, तब उसके खिलाफ पक्के सबूत के साथ शिकायत करें, तभी उस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। योगी ने विधायकों को क्षेत्र की जनता से बराबर संवाद बनाए रखने और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनने की भी सलाह दी है। वहीं एक विधायक द्वारा हेलमेट की जांच पर पुलिस द्वारा परेशान करने की शिकायत पर योगी ने कहा कि हेलमेट सुरक्षा के लिए जरूरी है। कानून का पालन हर हाल में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा इसलिए 10 साल से सत्ता से बाहर है,क्योंकि सपा सरकार में कानून का पालन नहीं होता था।

आयुष्मान भारत योजना..मृतक मरीजों के नाम पर बीमा दावे स्वीकृति

लोकलेखा समिति ने रिपोर्ट में किया खुलासा

नई दिल्ली (ईएमएस)। संसद की लोकलेखा समिति ने आयुष्मान भारत की पीएम जय योजना में क्लेम को लेकर बड़ा खुलासा किया है। लोकसभा में पेश समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना के तहत होने वाले लेन-देन पर निगाह रख रहे ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) ने इसतरह 88,760 मरीजों के नाम पर बीमा दावे स्वीकृत होने दिए, जिन्हें मृत बताया गया।

समिति ने 2.14 लाख फर्जी क्लेम के बारे में सवाल किया, तब जवाब दिया कि टीएमएस के अपडेट वर्जन में इसतरह के दावे पकड़ने की पुख्ता व्यवस्था की गई है। मरीज की मृत्यु होने के बाद अगर किसी प्रकार के दावे की पूर्व अनुमति होगी, तब उसके कारणों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। बता दें कि समिति कैग की ऑडिट जांच की रिपोटों में उठाए गए मुद्दों की पड़ताल करती है। कैग ने आयुष्मान भारत के प्रदर्शन को लेकर रिपोर्ट संसद को सौंपी थी। इस पर संज्ञान लेकर समिति ने स्वास्थ्य मंत्रालय की पीएम जय योजना की विसंगतियों की पड़ताल की। समिति ने मंत्रालय से पूछा है कि 2.14 लाख दावों पर क्या कदम उठाए, क्योंकि ऑडिट में सिर्फ कुछेक मामले ही जांचते हैं। इसतरह के मृतकों के नाम पर दावे लेने के मामले और भी ज्यादा हो सकते हैं। समिति ने बीमा कंपनियों के रिफंड न मिलने पर भी कड़ी टिप्पणियां की हैं। ऑडिट में पाया गया कि इस तरह के मामलों में 6 राज्यों में 700 करोड़ का रिफंड कंपनियों पर बकाया था। इसमें 241.91 करोड़ की वसूली कर ली

बुलडोजर बाबा की सक्रियता देख........विरोधियों के साथ अपने भी हुए हैरान उपचुनाव में जीत हासिल करने जुट गए योगी

लखनऊ (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस सक्रियता से काम कर रहे हैं, यह देख कर उत्तर प्रदेश भाजपा ही नहीं बल्कि पार्टी के केंद्रीय नेता भी हैरान हैं।

बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के कुछ साथियों के साथ बैठक कर उन्हें इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए कुछ जिम्मेदारियां दी थीं। उसके बाद से मुख्यमंत्री रोजाना इन मंत्रियों के साथ संवाद कर उपचुनाव वाली सीटों की जमीनी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों में यूपी में भाजपा को जो नुकसान उठाना पड़ा उसके चलते मोदी सरकार स्पष्ट बहुमत से पीछे रही और राज्य में योगी की विजेता वाली छवि भी प्रभावित हुई। इसके अलावा, योगी को इसकी भी चिंता है कि लोकसभा चुनाव परिणामों ने अन्य राज्यों में उनकी छवि को भी प्रभावित किया है। बता दें कि यूपी की कानून व्यवस्था को देखकर अन्य राज्यों की जनता अक्सर योगी जैसे मुख्यमंत्री की मांग करती है। योगी की बुलडोजर नीति का अनुसरण कई राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। योगी जब भी किसी अन्य राज्य में जाते हैं, तब उनका अक्सर बुलडोजरों से स्वागत किया जाता है। लेकिन लोकसभा चुनावों में यूपी में भाजपा को जो नुकसान उठाना पड़ा इस सबसे स्वयं योगी की छवि भी प्रभावित हुई है। इसके बाद योगी एकदम एक्शन में हैं, और हर हालत में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतना चाहते हैं। योगी की आतुरता के मायने में भी अनोखी है कि चुनावों की तैयारी उन्होंने अपनी पार्टी से पहले ही शुरू कर दी। योगी ने अपने मंत्रियों के बीच उपचुनाव वाली सीटों की जिम्मेदारी बांटी, तब उसके बाद भाजपा की प्रदेश इकाई ने भी बैठक कर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय कर दीं ताकि चुनावों में जीत हासिल हो सके।

बताया जा रहा है कि योगी की पहल पर प्रदेश भर के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से यह भी पूछा गया है कि पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण क्या थे? बताया जा रहा है कि अब तक मिले 50000 सुझावों के आधार पर एक रिपोर्ट बना कर मुख्यमंत्री को दी गयी है जिसके बाद योगी फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक युवाओं के बीच नाराजगी देखी गई। इसलिए उपचुनावों की घोषणा से पहले ही पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि उपचुनावों की तारीखें सामने आने से पहले कई और बड़ी घोषणाएं होगी, जिससे माहौल पूरी तरह बदल सकता है।

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की इस सप्ताह दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक भी होनी है जिसमें प्रदेश में भाजपा को फिर से मजबूत करने का रोडमैप प्रस्तुत होगा।

जैश से जुड़े आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार

श्रीनगर (ईएमएस)। जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 जुलाई को आतंकियों के हमले में जूनियर कमीशंड ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हुए थे। इस हमले में आतंकियों की मदद करने वाले दो ओवर ग्राउंड वर्कर गुरुवार को गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे।

दोनों आतंकियों को खाने-पीने की चीजों के साथ ही वाई-फाई मुहैया कराते थे, ताकि आतंकी सीमा पार बैठे अपने हैंडल्स से बातचीत कर सकें। इन इलाकों के स्थानीय लोग आतंकियों की मदद करते हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान लियाकत और राज के रूप में हुई है। 8 जुलाई के बाद से आतंकियों को ढूंढने के लिए पुलिस ने 100 लोगों से पूछताछ की थी।

हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ी राहत

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री (सीएम) अरविंद केजरीवाल को राहत प्रदान करते हुए तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान अपनी कानूनी टीम के साथ दो अतिरिक्त मुलाकात करने की याचिका को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने यह देखते हुए आदेश पारित किया कि विशेष परिस्थितियों में विशेष उपायों की आवश्यकता होती है। बता दें कि इससे पहले निचली अदालत ने अतिरिक्त लीगल मीटिंग के लिए केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर ली।

यूपी पुलिस की रद्द परीक्षा अगस्त में होगी

लखनऊ (ईएमएस)। यूपी पुलिस की रद्द की गई सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो गया। परीक्षा अगस्त में 5 दिन- 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी। जन्माष्टमी के चलते 4 दिन का गैप रहेगा। हर दिन दो शिफ्ट में एग्जाम होंगे। यानी 10 शिफ्ट में पूरी परीक्षा होगी। एक शिफ्ट में करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। सिपाही भर्ती की यह परीक्षा इसी साल 17 और 18 फरवरी को प्रदेश के 75 जिलों में हुई थी। कई जगह पेपर लीक होने के बाद छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। एसटीएफ जांच में पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद योगी सरकार ने परीक्षा कैंसिल कर दी थी। एग्जाम में करीब 50 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सिपाही भर्ती परीक्षा यूपी पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसमें 60,244 सिपाही के पदों को भरा जाना है।

लोकसभा अध्यक्ष बिरला की सांसदों को चेतावनी, भूलकर भी आसन को चुनौती ना दें

नई दिल्ली (ईएमएस)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अभिजीत गंगोपाध्याय और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में गुरुवार को सदस्यों से कहा कि वे सदन की मर्यादा रखें और आसन को चुनौती नहीं दें। सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर कांग्रेस सदस्यों ने गंगोपाध्याय की आपत्तिजनक टिप्पणी का विषय उठाया।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा, कोई भी सदस्य सदन की गरिमा को चोट पहुंचाने वाली टिप्पणी करे, वे दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना था, सदस्य चाहे सत्तापक्ष का हो या विपक्ष का हो, अगर वे सदन की गरिमा को चोट पहुंचाने वाली टिप्पणी करते है, तब शब्दों को कार्रवाई से हटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उचित कार्रवाई करने या उचित टिप्पणी करने का अधिकार भी अध्यक्ष को है। रीजीजू के अनुसार, जब गंगोपाध्याय ने टिप्पणी की, तब वे लोकसभा में नहीं, बल्कि राज्यसभा में थे। बिरला ने कहा, इस सदन की एक मर्यादा है। उच्च परंपरा और परिपाटी रही है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि सदन में अपनी बात रखें, चर्चा में भाग लें, लेकिन कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करें जो संसद की मर्यादा और संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं हो।

बिरला का इशारा अभिषेक बनर्जी द्वारा सदन में की गई टिप्पणी की ओर था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्य जितना सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा रखते हैं, उतना ही उनके क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सदन में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेकर गंगोपाध्याय ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके वक्तव्य के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने गोडसे को लेकर कोई टिप्पणी की, इसपर पलटवार कर गंगोपाध्याय ने उनके लिए एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया जिसका विपक्षी सदस्यों ने विरोध कर माफी की मांग की।

दूसरी तरफ, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बजट पर चर्चा में भाग लेकर नोटबंदी और लॉकडाउन का उल्लेख किया था, तब लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा, वर्ष 2016 के बाद दो बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। आप बजट पर बात कीजिए। अध्यक्ष का इशारा 2019 और 2024 में हुए आम चुनावों में भी भाजपा नीत राजग के सत्ता में आने की ओर था। फिर बनर्जी ने किसी का नाम लिया, जिस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा खड़ा कर दिया।

इस पर बिरला ने कहा कि सदस्य उन लोगों के नाम नहीं लें जो सदन के अब सदस्य नहीं हैं। इस पर बनर्जी ने बिरला से कहा कि जब सत्तापक्ष के सदस्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लेते हैं या देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का नाम लेते हैं, तब आसन उस पर कुछ नहीं बोलता, यदि कोई आपातकाल की बात करे, तब अध्यक्ष चुप रहते हैं।

डूंगरपुर में रेल को डीरेल कर लूटने की वारदात का हुआ खुलासा : पांच गिरफ्तार।

डुंगरपुर (ईएमएस) राजस्थान का डूंगरपुर जिला इन दिनों अशांति और पथराव की वारदातो के चलते सुर्खियों में बना हुआ है। यहां पिछले छः महीनों में अलग स्थानों पर पथराव एक लूटपाट की घटनाओं के बीच पांच दिन पहले कोटाना में असारवा जयपुर ट्रेन को डी रेल करने की साजिश सामने आई, जिसका खुलासा गुरुवार को डूंगरपुर पुलिस ने किया। वही पथराव और लूटपाट की घटना को लेकर डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा और उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने जिले में बढ़ रही इन घटनाओं को लेकर मामला बुधवार को विधानसभा और संसद में भी उठाया था।

डूंगरपुर एसपी मोनिका सैन ने बताया कि 21 जुलाई की रात को असारवा से जयपुर जा रही ट्रेन को सदर थाना क्षेत्र के कोटाणा स्टेशन के पास अज्ञात बदमाशों ने ट्रेक पर लोहे के सरिए डालकर डी रेल करने की कोशिश की थी। रेलवे की ओर से दर्ज करवाए मामले की जांच के लिए एएसपी निरंजन चारण के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था। पुलिस टीम ने जांच और चालानशुदा अपराधियों से पूछताछ की। इस दौरान मुखबिर तंत्र से मिली जानकारी पर ददोडिया निवासी निलेश पुत्र कारुलाल कटारा, अविनाश पुत्र नारायणलाल कटारा, रोहित पुत्र बाबूलाल कटारा, अजय पुत्र जीवा कटारा और मुकेश पुत्र लक्ष्मण अहारी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एक नाबालिग को डिटेन किया गया। बदमाशों से पूछताछ की तो सभी ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। जिस पर पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एसपी मोनिका सैन ने बताया कि पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि ट्रेन को बेपटरी कर सवारियों से लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने ये योजना बनाई थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूरे मामले को लेकर डूंगरपुर रेलवे स्टेशन मास्टर ने मामला दर्ज कराया था।

खनिजों पर टैक्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा- राज्यों को भी है टैक्स लगाने का हक

खनिजों पर राज्यों को रॉयल्टी वसूलने का कानूनी अधिकार

नई दिल्ली (ईएमएस)। खनिजों पर टैक्स वसूलने के मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। सीजेआई ने कहा है कि बेंच ने 8:1 के बहुमत से फैसला किया है कि खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जाएगा। सीजेआई ने कहा है कि माइंस और मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट राज्यों की टैक्स वसूलने की शक्तियों को सीमित नहीं करता है। राज्यों को खनिजों और खदानों की जमीन पर टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार है। खदानों और खनिजों पर केंद्र की ओर से अब तक टैक्स वसूली के मुद्दे पर 31 जुलाई को सुनवाई होगी।

दरअसल, अलग-अलग राज्य सरकारों और खनन कंपनियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 86 याचिकाएं पहुंची थीं। कोर्ट को को तय करना था कि मिनरल्स पर रॉयल्टी और खदानों पर टैक्स लगाने के अधिकार राज्य सरकार को होने चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 8 दिन तक चली सुनवाई में केंद्र ने कहा था कि राज्यों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए। अदालत ने 14 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार केवल संसद को ही नहीं है, बल्कि राज्यों को भी दिया गया है। ऐसे में उनके अधिकार को दबाया नहीं जा सकता है। 9 जजों की बेंच में जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्जल भुइयां, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज शामिल थे। इनमें से जस्टिस बीवी नागारत्ना की बाकी जजों से अलग राय थी। बीवी नागरत्ना का मनना है कि राज्यों को टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं देना चाहिए। इससे इन राज्यों में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा।

केंद्र की दलील- महंगाई बढ़ेगी

केंद्र ने कहा था कि अगर राज्यों को टैक्स लगाने का अधिकार दिया तो राज्यों में महंगाई बढ़ेगी। खनन क्षेत्र में एफडीआई में दिक्कतें आएंगी। इससे भारतीय मिनरल्स महंगे होंगे और इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिशन घटेगा। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामा में खनिज पर रॉयल्टी से अधिक टैक्स लगाने का विरोध किया था। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया था- केंद्र के पास खदान और खनिजों पर टैक्स लगाने की ज्यादा शक्तियां हैं। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि खदान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम राज्यों को खनिजों पर टैक्स लगाने से रोकती है। मिनरल्स पर रॉयल्टी तय करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। खनन मंत्रालय ने भी कहा था कि बिजली, स्टील, सीमेंट, एल्यूमीनियम आदि के लिए कच्चा माल खनिजों से मिलता है। इसलिए अगर राज्यों ने रॉयल्टी से अलग टैक्स लगाया तो पूरे देश में महंगाई बढ़ेगी।

जन हितैषी

2024-25 के बजट से केंद्र सरकार बची, भाजपा के लिए अस्तित्व का संकट?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में प्रस्तुत हो गया है। इस बजट को लेकर देश मे बड़ी तीखी क्रिया-प्रतिक्रिया हो रही है। 2024-25 के केन्द्रोय बजट में सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की घोषणाएं की हैं। जिसके कारण अन्य राज्यों के साथ भेदभाव होने की बातें सामने आ रही है। संसद के दोनों सदनों में बजट का मुद्दा लगातार गर्मा रहा है। इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक दल बड़े मुखर होकर बजट का विरोध कर रहे हैं। इस बजट को जन विरोधी भी बताया जा रहा है। सरकार ने आंध्र और बिहार राज्य को विशेष पैकेज देने के लिए, जिस तरह से अन्य राज्यों की उपेक्षा मनरेगा एवं शिक्षा के बजट मे कटौती की है। उसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा का बजट बढ़ाने की बजाये कम कर दिया गया है। इसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पड़ेगा। शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए मनरेगा जैसी योजना लाने की मांग हो रही थी। इस बजट में शहरी मजदूरों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दो राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों को बजट मे कुछ भी नहीं मिला। सबकी थाली खाली करके 2 थालियों में सरकार ने पकोड़ा और जलेबी परोस दी है। उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को माता जी कहकर राज्यसभा में संबोधित किया। जो विपक्ष की पीड़ा को जग जाहिर कर रहा था। इस बयान की बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखने को मिली। विपक्ष ने संसद परिसर के बाहर जिस तरह एकत्रित होकर बजट का विरोध किया। सामूहिक रूप से नारेबाजी की। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया, सरकार संघीय व्यवस्था को भूलकर केवल सरकार बचाने के लिए बजट लेकर आई है। सदन के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष के सांसदों मे भी बजट को लेकर निराशा देखने को मिल रही है। देश के कई राज्यों में डबल इंजन की भाजपा सरकारें हैं। इस बजट में उन राज्य सरकारों की भी उपेक्षा हुई है। जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं। उनकी भी बजट मे उपेक्षा हुई है। इस बजट से भाजपा के सांसद और भाजपा शासित राज्यों के विधायक भी मायूस हैं। 2024-25 के बजट में जिस तरह से आंध्र और बिहार को अतिरिक्त राशि दी गई है। वहीं अन्य राज्यों के मनरेगा और शिक्षा के बजट में कमी की गई है। नए बजट में 2 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों को कुछ नहीं मिला है,जिसकी वह आशा कर रहे थे। ऐसी स्थिति में भाजपा शासित राज्यों के सांसदों और विधायकों के लिए मतदाताओं को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। डबल इंजन के सरकारों को भरोसा था, इस बजट में उन्हें ज्यादा आर्थिक सहायता मिलेगी। डबल इंजन की राज्य सरकारों के मुखिया अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगले कुछ महीनो में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव होने हैं। आंध्र और बिहार को विशेष पैकेज देने के कारण, जिन राज्यों में अगले कुछ महीनो में चुनाव होना है। वहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से कमजोर है। रही-सही कसर इस बजट ने आग में घी डालने जैसा काम कर दिया है। बजट में जिस तरह से मध्यम वर्ग के ऊपर कैपिटल गेन एवं संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस काटने जैसे प्रावधान बजट मे होने से मध्यमवर्गीय परिवारों में तीखा विरोध हो रहा है। इस बजट से राज्यों के साथ भेदभाव का मामला तूल पकड़ने लगा है। विपक्ष कह रहा है,कि केंद्र सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमिलनाडु,केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की भारी उपेक्षा की है। इस बजट का यह संदेश देश भर में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा। इसका अंदाजा सरकार को नहीं रहा होगा। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं,उनकी भी स्थिति बजट आने के बाद कमजोर हुई है। जिन राज्यों के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन देकर चुनाव जिताया है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में पहली बार 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है। उन राज्यों को भी बजट में कुछ नहीं मिला। आम जनता की नाराजी होना स्वाभाविक है। बहरहाल केंद्रीय बजट पेश हो गया है। इस पर दोनों सदनों में चर्चा भी शुरू हो गई है। इस बजट के बारे में देश भर से क्रिया प्रतिक्रिया मिलना शुरू हो गई है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। जिन राज्यों में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। केंद्र की मोदी सरकार बचाने के लिए, सरकार ने भाजपा को ही दांव पर लगा दिया है, यह कहा जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट के कारण पहले भी भाजपा नाराजी का शिकार हो रही थी। इस बजट ने एक तरह से नाराजी की आग में घी डालने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गठबंधन की सरकार का यह पहला अनुभव है। गुजरात में जब वह मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से ही वहां पर स्पष्ट बहुमत की सरकार रही हैं। 2014 तथा 2019 की केंद्र सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके कारण मोदी सरकार की राजनीतिक चुनौती बढ़ी हुई हैं। इस बजट ने उनकी चुनौतियों को और भी बढ़ा दिया है। मोदी सरकार के लिए यह कार्यकाल तलवार की धार में चलने के समान है। जरा सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। इसका ध्यान केंद्र सरकार और भाजपा को रखना होगा।

प्रतिबंध मुक्त संघ एक नयी किरण का आगाज

केंद्र की राजग सरकार ने एक महत्वपूर्ण एवं साहसिक आदेश के जरिये सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक को हटा कर लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक भावना एवं मूल्यों का जीवंत किया है। भले ही इस आदेश को लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों की तल्ख प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं संघ ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि तत्कालीन सरकार ने निराधार ही शासकीय कर्मियों के संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगायी थी। निश्चित ही वर्तमान सरकार का यह निर्णय लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक गैर-राजनीतिक संगठन है, गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न संघ एक रचनात्मक, सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक संगठन है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता-अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में संघ के योगदान की विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के नेताओं एवं दलों ने प्रशंसा भी की है। इस नये आदेश को लेकर इंडी गठबंधन के दलों में खलबली एवं बौखलाहट का सामने आना स्वाभाविक है, क्योंकि इस आदेश से संघ की ताकत बढ़ेगी, जो इन विपक्षी दलों की चिन्ता का बड़ा कारण है।

दरअसल, आरोप है कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों की संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था। सेवानिवृत होने के बाद पेंशन लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए भी अनेक सरकारी कर्मचारी चाहते हुए भी संघ की गतिविधियों में शामिल होने से बचते थे। हालांकि, इस बीच मध्यप्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार के स्तर पर यह वैध बना हुआ था। इस मामले में एक वाद इंदौर की अदालत में चल रहा था, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से सफाई मांगी थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने नौ जुलाई को एक ऑर्डर जारी करते हुए उक्त प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा कर दी। निश्चित ही यह आदेश संघ से जुड़े एवं राष्ट्रीय विचारधारा वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये एक नयी किरण है।

आपातकाल में इंदिरा गांधी सरकार की तानाशाही खुलकर सामने दिखी थी, लेकिन उससे पहले भी तानाशाही कदम उठाए जाते रहे थे। दरअसल, 7 नवंबर 1966 को संसद के सामने गोहत्या के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। 30 नवंबर 1966 को संघ-जनसंघ के प्रभाव से हिलकर इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के संघ में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि संघ व जनसंघ के प्रयासों से लाखों लोग जुटे थे और पुलिस के साथ टकराव में कई लोगों की जान गई थी। गोलीबारी में सैंकड़ों निर्दोष साधु-संत मारे गये थे। इस जघन्य हत्याकांड से क्षुब्ध होकर तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस पार्टी ने 58 साल पहले वर्ष 1966 में संघ पर लगाये गए प्रतिबंध को हटाने के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। कहा जा रहा है कि जनसंघ, वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार की पिछली एक दशक की सरकार के दौरान भी यह प्रतिबंध नहीं हटाया गया था, फिर अभी हटाने के पीछे गहरी राजनीतिक चाल है। वहीं संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर का कहना है कि संघ पिछले 99 साल से राष्ट्र के सतत निर्माण व समाज सेवा में संलग्न रहा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते तत्कालीन सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने हेतु निराधार प्रतिबंधित किया था।

क्रांति का फलित है व्यापक स्तर पर होने वाला कोई बड़ा परिवर्तन। व्यक्ति जिस समाज में जीता है, उसकी व्यवस्थाओं, नीतियों और परम्पराओं में जब घुटन का अनुभव करता है जो वह किसी नए मार्ग का अनुसरण करता है। आज आजादी के बाद की राजनीतिक विसंगतियों से पनपी ऐसी ही घुटन से बाहर निकालने के प्रयत्न वर्तमान सरकार द्वारा हो रहे हैं। ऐसा ही एक विशिष्ट उपक्रम है सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध का हटना। इसको लेकर भी विपक्षी दलों द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है, राष्ट्र की एकता को विखंडित करने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने संघ की गतिविधियों में कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाकर नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की है। निःसंदेह, सरकार का यह निर्णय लोकतंत्र और संविधान की भावना को मजबूत करनेवाला है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह विविध सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों में शामिल हो सके। एक सामान्य नागरिक की भांति यह अधिकार कर्मचारियों को भी प्राप्त है कि अपने कार्यालयीन समय के बाद सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा हो सकते हैं। परंतु, लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देनेवाली कांग्रेस की सरकार ने तानाशाहीपूर्ण तरीके से संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो एक प्रकार से राष्ट्रीय विचार के प्रति झुकाव रखनेवाले लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास ही था। कांग्रेस की नीयत को समझिए कि उसने ऐसा कोई प्रतिबंध इस्लामिक, ईसाई, कम्युनिस्ट और अन्य प्रकार के संगठनों की गतिविधियों में शामिल होने पर नहीं लगाया था। यानी कर्मचारी इस्लामिक एवं ईसाई संगठनों से जुड़ सकता था लेकिन हिन्दू संगठन की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता था। कांग्रेस की इस तानाशाही एवं द्वेष का उत्तर संघ ने तो कभी नहीं दिया लेकिन समाज ने अवश्य ही कांग्रेस को आईना दिखाने का कार्य किया।

कांग्रेस लगातार आठ दशकों में हिन्दू-संस्कृति को कमजोर करने की राजनीतिक चालें चलती रही है। जबकि हिन्दू धर्म नहीं, विचार है, संस्कृति है। हिन्दू राष्ट्र होने का अर्थ धर्म से न होकर हिन्दू संस्कृति के सर्वग्राही भाव से है। हिन्दू संस्कृति उदारता का अन्तर्निहित शंखनाद है क्योंकि पूरे विश्व में यह अकेली संस्कृति है जो बहुविचारवाद यानी सभी धर्म, विचार एवं संस्कृतियों को स्वयं में समेटे हैं। हमारे ऋषियों ने हमें यह उपदेश दिया कि 'सत्यं बूर्यात न बूर्यात सत्यं अप्रियं' अर्थात सच बोलो मगर कड़वा सच मत बोलो। हिन्दू संस्कृति की यही महानता और विशेषता रही है कि प्रिय सत्य की वकालत तो करती है मगर इसके कटु होने पर निषेध करने को भी कहती है। यह हिन्दू संस्कृति अहिंसा की संस्कृति है पर जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाकर स्व-रक्षा की बात भी कहती है। हिन्दू शब्द से ही स्वराष्ट्र का बोध होता है जो कि हिन्दू संस्कृति के वृहद स्वरूप का ही सौपान है। लेकिन राजनीतिक कारणों से कांग्रेस एवं अन्य ताकतों ने हिन्दू संस्कृति को निस्तेज करने, संघ को दबाने एवं समाप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। इस आदेश के अतिरिक्त तीन बार संघ पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया। संघ की छवि खराब करने के लिए बड़े-बड़े नेताओं की ओर से मिथ्या प्रचार भी किया गया। अपने समर्थक बुद्धिजीवियों से पुस्तकें भी लिखवायी गईं। लेकिन निस्वार्थ भाव से देश और समाज के लिए कार्य करनेवाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई रोक नहीं सका।

अपनी 99 वर्ष की यात्रा में संघ ने लगातार प्रगति एवं विस्तार ही किया है। अपने विचार, आचरण एवं सेवाकार्यों से संघ ने समाज का विश्वास जीता, जिसके कारण समाज सदैव संघ के साथ खड़ा रहा। कांग्रेस सरकार का तात्कालिक आदेश भी सरकारी कर्मचारियों को संघ कार्य में सहभागी होने से रोक नहीं सका। कई ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें संघ गतिविधि में शामिल होने पर कांग्रेस की सरकारों ने सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की। लेकिन वे सभी मामले न्यायालय में टिक नहीं सके। संघ के स्वयंसेवक न्यायालय से जीतकर आए। उनकी छोटी-छोटी जीतों की श्रृंखला ने भी यह साबित किया कि संघ की गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए लगाया गया कांग्रेस सरकार का आदेश निरर्थक और संविधान एवं मौलिक अधिकारों की मूल भावना के विरुद्ध था। (लेखक- ललित गर्ग / ईएमएस)

केंद्र सरकार द्वारा बजट के माध्यम से भारत में रोजगार के नए अवसर निर्मित करने एवं आर्थिक विकास को गति देने का प्रयास किया गया है

हाल ही में लोकसभा के लिए सम्पन्न हुए चुनाव में भारतीय नागरिकों ने लगातार तीसरी बार एनडीए की अगुवाई में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सत्ता की चाबी आगामी पांच वर्षों के लिए इस उम्मीद के साथ पुनः सौंपी है कि आगे आने वाले पांच वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा देश में आर्थिक विकास को और अधिक गति देने के प्रयास जारी रखे जाएंगे। भारत की वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 23 जुलाई 2024 को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट भारतीय संसद में पेश किया है। इस बजट के माध्यम से भारत की आर्थिक विकास दर को उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास किया गया है।

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 9 प्राथमिकताएं तय की है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाना, युवाओं के लिए रोजगार के अधिकतम अवसर निर्मित करना एवं उनके कौशल को विकसित करना, गरीब नागरिकों को भी विकास में हिस्सेदारी देना एवं उन्हें सामाजिक न्याय देना, विनिर्माण इकाईयों को बढ़ावा देना, शहरी क्षेत्रों को विकसित करना, ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आधारभूत ढांचा विकसित करना, नवाचार, शोध एवं विकास करना तथा नई पीढ़ी के सुधार कार्यक्रमों को लागू करना।

केंद्र सरकार एवं कुछ राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत खर्चों में लगातार की जा रही वृद्धि के चलते भारत की आर्थिक विकास दर को पंख लगते दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 2022-23 के बजट में केंद्र सरकार द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किया गया था, वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसमें 33 प्रतिशत की भारी भरकम वृद्धि करते हुए इसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया था। अब वित्तीय वर्ष 2024-45 के लिए इसे और आगे बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में न केवल स्थिरता दिखाई देने लगी है बल्कि यह लगातार तेज गति से आगे बढ़ रही है। आज पूरे विश्व में केवल भारतीय अर्थव्यवस्था ही एक चमकते सितारे के रूप में दिखाई दे रही है।

बजट का गहराई से अध्ययन करने पर ध्यान में आता है कि केंद्र सरकार ने अब भारत में रोजगार के अधिकतम अवसर निर्मित करने की ठान ली है। भारत के युवाओं एवं महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं कौशल विकसित करने की दृष्टि से 2 लाख करोड़ रुपए की 5 योजनाओं के एक पैकेज की घोषणा की है। शिक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए की राशि इस बजट में आबंटित भी कर दी गई है। प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत ईंइध के प्रथम बार सदस्य बनने पर औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के ईंइध खातों में एक माह का वेतन जमा किया जाएगा। इन कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के अंतर्गत एक माह का वेतन (15000 रुपए की अधिकतम राशि तक) तीन किश्तों में उनके खातों में जमा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक माह में एक लाख रुपए तक का वेतन पाने वाली कर्मचारी ही पात्र होंगे। इससे 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ होने की सम्भावना बजट में व्यक्त की गई है।

ऐसे भी कई निर्णय लिए जा रहे हैं जिनसे आने वाले समय में धरातल पर युवाओं को लाभ होता दिखाई देगा। एक करोड़ युवाओं को आगामी 5 वर्षों के दौरान इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत काम दिया जाएगा। ताकि ये युवा वर्ग के नागरिक रोजगार प्राप्त करने हेतु सक्षम हो सकें। इन युवाओं को प्रति माह 6,000 रुपए तक का वाजीफा सम्बंधित कम्पनियों द्वारा अदा किया जाएगा। वजीफे की इस राशि को कम्पनियों के लिए लागू निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अंतर्गत किया गया खर्च माना जाएगा। भारत की सबसे बड़ी 500 कम्पनियों को इस योजना के अंतर्गत युवाओं को इंटर्नशिप की सुविधा देनी होगी। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा भी इन युवाओं को प्रतिमाह 5000 रुपए अदा किए जाएंगे। यह केंद्र सरकार का एक सूझबूझ भरा निर्णय कहा जा सकता हैं। साथ ही, विनिर्माण के क्षेत्र के रोजगार के नए अवसर निर्मित करने की पहल भी की जा रही है। नए कर्मचारियों के ईंइध खाते में जमा होने वाली राशि को आगामी 4 वर्षों तक केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, इससे कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों को ही लाभ होगा। इस योजना का लाभ 30 लाख युवाओं को होने जा रहा है। एक अन्य योजना के अंतर्गत नियोक्ता को अपने नए कर्मचारियों के ईंइध खातों में जमा की जाने वाली राशि की प्रतिपूर्ति आगामी 2 वर्षों तक केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इससे रोजगार के 50 लाख नए अवसर निर्मित होने की सम्भावना है।

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही के समय में भारतीय सनातन संस्कृति के संस्कारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धार्मिक पर्यटन को देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन से देश में रोजगार के लाखों अवसर निर्मित हो रहे हैं एवं गरीब वर्ग की आय में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। श्री विष्णुपाद मंदिर कोरिडोर, गया, बिहार एवं श्री महाबोधि मंदिर कोरिडोर बोधगया, बिहार को विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। इसे काशी विश्वनाथ मंदिर कोरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार देश में अन्य मंदिरों को भी विकसित किया जा रहा है ताकि देश में इन मंदिरों में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो तथा भारत को वैश्विक पटल पर एक बहुत बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में दिखाया जा सके।

भारत के ग्रामों में निवास कर रहे नागरिक रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से शहरों की ओर पलायन करते हैं। अतः ग्रामों में ही रोजगार के अधिकतम अवसर निर्मित करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास की मद पर 2.66 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। साथ ही, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ऋण राशि की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। यह सुविधा तरुण श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त ऋण के व्यवसाईयों को प्राप्त होगी एवं जिन्होंने पूर्व में लिए गए 10 लाख रुपए के ऋण की राशि को समय पर अदा कर दिया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए भी ऋण की सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत एक करोड़ आवासों का निर्माण किया जाएगा। इन एक करोड़ आवासों पर 10 लाख करोड़ रुपए की राशि का निवेश होगा, इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी 2.2 लाख करोड़ रुपए की रहेगी। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 3 करोड़ आवासों का निर्माण करने की घोषणा पूर्व में ही की जा चुकी है।

देश के आर्थिक चक्र को गति देने के उद्देश्य से नई कर प्रणाली के अंतर्गत वेतनभोगी/पेंशनधारी कर्मचारियों के लिए सामान्य छूट की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही, आय कर की दरों में कुछ इस प्रकार का संशोधन किया गया है कि 15 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 17,500 रुपए का लाभ होगा। इस निर्णय से मध्यम वर्गीय नागरिकों के हाथों में कुछ अधिक राशि बचेगी और इस राशि इस इनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी ताकि देश की अर्थव्यवस्था के चक्र में मजबूती आएगी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में कुल आय का अनुमान रुपए 31.07 लाख करोड़ रुपए का लगाया गया है, इसमें ऋण की राशि शामिल नहीं है परंतु, करों के मद से प्राप्त होने वाली 25.83 लाख करोड़ रुपए की राशि शामिल है। जबकि, कुल खर्च का अनुमान 48.21 लाख करोड़ रुपए का लगाया गया है। (लेखक - प्रहलाद सबनानी / ईएमएस) (सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक)

आखिर संसद का मौसम गड़बड़ क्यों ?

संसद के बजट सत्र का मौसम खराब हो रहा है। खासतौर पर लोकसभा का मौसम ठीक नहीं दिखाई दे रहा। तृण मूल कांग्रेस ने तो खराब मौसम की चेतावनी देते हुए सत्ता पक्ष से अपनी-अपनी कुर्सियों की पेटी बाँधने के लिए कहा है। हिचकोले खाती संसद में लोकसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष के सर पर छाता ताने खड़े रहना चाहते हैं ,ताकि सरकार विपक्ष के बादलों के बरसने पर ज्यादा भींगे नहीं।

लोकसभा में अध्यक्ष पद पर श्री ओम बिरला का ये दूसरा कार्यकाल है। वे संसद को कैसे चला रहे हैं ,इसके बारे में किसी टिप्पणी की जरूरत नहीं है। ये जानने के लिए सदन की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है । सदन प्रमुख होने के नाते बिरला जी न तो विपक्ष को संरक्षण दे पा रहे हैं और न सत्ता पक्ष की हीढंग से चाकरी कर पा रहे हैं। लोकसभा के इतिहास में ओम जी किस रूप में दर्ज किये जायेंगे ,ये कहना कठिन है।

लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय बजट 2024 पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला में तीखी नोकझोंक से इस बात के संकेत एक बार फिर मिले की ओम बिरला जी सदन चलने में असुविधा का अनुभव कर रहे है। विपक्षी सांसदों के बोलते ही लोकसभा अध्यक्ष को लगता है कि वे सरकार के दुश्मन हैं। तृण मूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने चर्चा के दौरान दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं की जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया था । अभिषेक बनर्जी के दावे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई और कहा कि इस सदन में तीन कृषि कानूनों पर करीब साढ़े पांच घंटे तक चर्चा हुई। बिरला की दावे पर अभिषेक ने जोर देकर कहा कि चर्चा नहीं हुई तो स्पीकर बोले कि जब अध्यक्ष बोलते हैं तो सही ही बोलते हैं और आपको रिकॉर्ड देखना चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रति जैसी थी ठीक वैसा ही वे तृण मूल कांग्रेस के अभिषेक के साथ कर रहे हैं। सत्ता के खिलाफ बोलते ही सत्ता पक्ष की और से लोकसभा अध्यक्ष खुद बचाव की मुद्रा में बोलना शुरू कर देते हैं। वे अक्सर भूल जाते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष किसी दी का नहीं बल्कि सभी सांसदों के हितों का संरक्षक होता है। मेरे दिमाग में लोकसभा अध्यक्ष की जो छवि है उसमें पता नहीं क्यों बिरला जी समा नहीं रहे हैं। वे अक्सर संघ की शाखा प्रमुख के हिसाब से बर्ताव करने दिखाई देते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है की उन्होंने संघ की शाखाओं में केंद्रीय कर्मचारियों पर लगे प्रतिबंध की समाप्ति को अपने ऊपर भी लागू कर लिया है।

चर्चा के दौरान अभिषेक बनर्जी ने 2016 में की गई नोटबंदी का जिक्र किया जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पर बात करें क्योंकि 2016 के बाद तो काफी समय निकल गया, इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कोई पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की बात बोलेगा तो आप कुछ नहीं कहेंगे और मैं 2016 की नोटबंदी की बात कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि वर्तमान बजट पर बोलिए। अभिषेक बनर्जी बोले कि ये पक्षपात नहीं चलेगा क्योंकि जब कोई इमरजेंसी के मुद्दे को उठाता है तो आप चुप रहते है। किसी भी लोकसभा अध्यक्ष के लिए ये लज्जा की बात है की सदन का कोई भी सदस्य उनके ऊपर पक्षपात का आरोप लगाए। दुर्भाग्य से ओम जी के साथ ऐसा हर दिन हो रहा है।

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सदन की नेता सुमित्रा महाजन रहीं। उनसे पहले सुश्री मीरा कुमार ने भी सदन को सुचारु रूप से चलाया। यहां तक की वामपंथी सोमनाथ चटर्जी के कार्यकाल में भी लोकसभा अध्यक्ष की मर्यादा पर ज्यादा सवाल नहीं उठाये गए ,क्योंकि किसी ने भी खुद को सत्तापक्ष का स्पीकर बनाने की गलती नहीं की।भाजपा के मनोहर जोशी भी लोकसभा के सम्मानित अध्यक्ष रहे । कांग्रेस के पीए संगमा तो सबसे जायदा विनोदी लोकसभा अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में कभी भी सदन में तनाव देखा ही नहीं गया । यहां तक कीटीडीपी के जीएमसी बालकृष्ण योगी ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में एक यादगार भूमिका अदा की। मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी इस परम्परा को आगे बढ़ाने में हिचकोले खा रहे हैं।

अभिषेक बनर्जी ने संबोधन के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए सिर्फ इतना कहा कि गठबंधन का मतलब समन्वय होता है और कोई भी उसे मोदी 3.0 नहीं कह रहा। इस सरकार को खुद बीजेपी के मंत्री भी मोदी 3.0 नहीं कर रहे है। ये सरकार काफी अनिश्चित और नाजुक है और कभी भी गिर सकती है । उन्होंने कहा कि सब्र रखिए और कुर्सी की पेटी भी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। बनर्जी ने ये बात भी विनोद में कही है और इसे विनोद की तरह ही लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

आपको याद होगा कि माननीय ओम बिरला जी के खाते में सदन के सर्वाधिक सदस्यों को निलंबित करने का आधिकारिक रिकार्ड है। सदस्यों का निलंबन सबसे आखरी विकल्प होता है । सवाल ये है कि जिस भूमिका में ओम जी पिछली लोकसभा में थे वैसे ही क्या वे इस लोकसभा में रह सकते हैं ? मौजूदा लोकसभा में न सत्ता पक्ष प्रचंड बहुमत वाला है और न ही विपक्ष पहले कि तरह कमजोर और बिखरा हुआ है। इस बार विपक्ष को पहले कि तरह सामूहिक निलंबन की सजा नहीं सुनाई जा सकती। बेहतर तो यही है कि ओम जी हिकमत अमली से काम लें। सरकार के साथ विपक्ष को भी दुलारें ,पुचकारें ,हिकमत अमली से काम लें ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटने पाए।

दुर्भाग्य से देश की राजनीति में सौहार्द के स्थान पर अदावत मजबूत होती जा रही है । इसे समाप्त करने या कम करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में पुल का काम कर सकते हैं। लोकतंत्र में अदावत और पक्षपात के लिए सीमित जगह होती है ,इसे प्रोत्साहित करना लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा है।(लेखक - राकेश अचल / ईएमएस)

खेल-समाचार

भारतीय महिला तीरंदाजी टीम पेरिस ओलंपिक के क्वार्टरफाइनल में पहुंची

पेरिस (ईएमएस)। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक की तीरंदाजी स्पर्धा के क्वार्टरफाइनल में जगह बनायी है। भारतीय तीरंदाजों दीपिका कुमारी समेत भजन कौर और अंकिता भकत ने महिला व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारत को क्वॉर्टर फाइनल में पहुंचाया। दीपिका , अंकिता और भजन ने कुल मिलाकर भारत को 1,983 अंक दिलाए हैं।

दीपिका , भजन और अंकिता ने महिला व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में भाग लेते हुए अपने प्रदर्शन से भारत को क्वॉर्टर फाइनल का टिकट दिलाया। वहीं टीम रैंकिंग के हिसाब से भारतीय टीम इस राउंड के बाद चौथे स्थान पर रही। इस दौरान भारत के 1983 अंक रहे, जबकि कोरिया 2046 अंकों के साथ ही शीर्ष पर रहा। वहीं चीन 1996 और मैक्सिको 1986 की टीम को दूसरा और तीसरा स्थान मिला।

वहीं यक्तिगत स्कोर की बात करें तो भारत की ओर से अंकिता पहले स्थान पर रही। अंकिता ने 72 शॉट लगाते हुए कुल 666 अंक हासिल किए हैं और वे 11वें स्थान पर रहीं जबकि भजन और दीपिक टॉप-20 से बाहर रहकर 22 वें और 23 वें स्थान पर रहीं।

बिंद्रा को मिला ओलिंपिक ऑर्डर

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने एक अहम उपलब्धि हासिल की है। अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आईओसी) ने ओलिंपिक को आगे बढ़ाने (ओलिंपिक मूवमेंट) में बिंद्रा के विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें ओलिंपिक ऑर्डर दिया है। इस अहम उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिंद्रा की प्रशंसा की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिंद्रा को ओलिंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा, अभिनव को ओलिंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। उन्हें बधाई। चाहे एथलीट के रूप में हो या आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक संरक्षक के रूप में उन्होंने खेलों व ओलिंपिक मूवमेंट में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ओलिंपिक आर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने पर अभिनव बिंद्रा को बधाई। अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी, अभिनव बिंद्रा अपने ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन से एथलीटों को प्रेरित करते रहते हैं। मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बिंद्रा ने बीजिंग ओलिंपिक में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता था।

ओलिंपिक ऑर्डर पुरस्कार किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला सर्वोच्च ओलिंपिक सम्मान है। बिंद्रा ये सम्मान हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। ओलिंपिक ऑर्डर सम्मान की स्थापना 1975 में हुई थी। शुरुआत में यह पुरस्कार गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कैटेगरी में विशिष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता था। 1984 में समीक्षा के बाद आईओसी ने सिल्वर और ब्रॉन्ज की कैटेगरी को समाप्त कर दिया। इसके बाद यह तय किया कि अब यह पुरस्कार सिर्फ गोल्ड कैटेगरी में ओलिंपिक खेलों में विशिष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को ही दिया जाएगा। आईओसी ओलिंपिक की मेजबानी करने वाले राष्ट्र प्रमुखों को भी यह पुरस्कार देता रहा है। परंपरागत रूप से आईओसी प्रत्येक ओलिंपिक गेम्स के समापन समारोह में यह सम्मान वितरित किया जाता रहा है , इसबार ये 10 अगस्त को दिया जाएगा। दुनिया में अब तक 116 हस्तियों को गोल्ड ओलिंपिक ऑर्डर पुरस्कार मिल चुका है।

पेरिस ओलंपिक में भारतीय टेबल टेनिस टीम का पहला मुकाबला चीन से होगा

पेरिस (ईएमएस)। पेरिस ओलंपिक की टेबल टेनिस स्पर्धा में भारत का पहला मुकाबला चीन से होगा। आयोजन समिति ने इवेंट के ड्रॉ की घोषणा कर दी है। इसमें भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम को शुरुआती दौर में चीन से टक्कर लेनी होगी। वहीं महिला टीम का सामना रोमानिया से होगा। इसके बाद दूसरे राउंड में उसका सामना जर्मनी से हो सकता है।

भारतीय टीम ने पहली बार टेबल टेनिस में टीम स्पर्धाओं के लिए क्वालीफाई किया है। दूसरी ओर, चीन ने 2008 में ओलंपिक में टीम स्पर्धाओं की शुरुआत के बाद से सभी संस्करणों में पुरुष स्पर्धा में जीत हासिल की है। महिला एकल स्पर्धा में भारत की उम्मीदें स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा पर टिकी रहेंगी। मनिका को इसमें 18वीं वरीयता दी गई है। वह ब्रिटेन की अन्ना हर्सी के खिलाफ अपना अभियान शुरु करेंगी।

वहीं एक अन्य भारतीय श्रीजा अकुला को 16वीं सीड दी गई है और वह स्वीडन की क्रिस्टीना कल्बर्ग से खेलेंगी। पुरुष एकल में अनुभवी शरत कमल पहले दौर में स्लोवेनिया के डेनी कोजुल से मुकाबला करेंगे जबकि भारत के ही हरमीत देसाई 27 जुलाई को जॉर्डन के जैद अबो यमन से मुकाबला करेंगे।

फ्रांस अमेरिका करेंगे 2030 और 2034 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी

पेरिस (ईएमएस)। फ्रांस को 2030 और अमेरिका को 2034 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है। अंतराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने फ्रांस के फ्रेंच आल्प्स और अमेरिका के साल्ट लेक सिटी को दिये जाने की बात कही है। फ्रांस को मेजबानी हालांकि कुछ शर्तों के आधार पर मिली है। ये शर्त है कि उस समय जो भी सरकार होगी वह आयोजन से संबंधित सभी शर्तों को पूरा करेगी। ऐसे में फ्रांस में नई सरकार के गठन के बाद जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उसे इन शर्तों को मानना होगा। आईओसी ने करार पर हस्ताक्षर के लिए एक अक्टूबर की समय सीमा तय की है। आईओसी के सदस्यों ने फ्रांस सरकार के इस करार को मानने के आश्वासन को स्वीकार करके फ्रांस को मेजबानी सौंपी है। फ्रांस की मेजबानी के पक्ष में 84 सदस्यों ने जबकि चार सदस्यों ने विरोध में मतदान किया था जबकि सात सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रों ने कहा, 'हम पर भरोसा दिखाने के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम अपनी प्रतिबद्धताओं का पूरा सम्मान करेंगे। फ्रांस इन खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाने वाला एकमात्र देश था। फ्रांस ने इससे पहले तीन बार 1924, 1968 और 1992 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। आईओसी सदस्यों ने इसके बाद 2034 में होने वाले शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए साल्ट लेक सिटी की बोली पर भी मोहर लगाई।

साल्ट लेक सिटी को 32 साल के अंतराल के बाद इन खेलों के आयोजन का अवसर मिलेगा। इससे पहले उसने 2002 में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी।

नीता अंबानी लगातार दूसरी बार आईओसी सदस्य बनीं

पेरिस (ईएमएस)। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी लगातार दूसरी बार अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) सदस्य बनी हैं। नीता को पेरिस में सर्वसम्माति से दूसरी बार भारत से आईओसी का सदस्य चुना गया। आईओसी के 142वें सत्र के दौरान हुए मतदान में नीता को पूरे सौ फीसदी मत मिले। नीता के आईओसी में शामिल होने से अब भारतीय खेल संघों को भी वैश्विक स्तर पर सहयोग और समर्थन मिलने लगेगा।

वहीं नीता ने दोबार आईओसी सदस्य चुने जाने के बाद कहा, ''मैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में फिर से चुने जाने पर बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं। मैं आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक और आईओसी में अपने सभी सहयोगियों को मुझ पर भरोसे जताने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं।

शब्द पहेली - 8079

बाएँ से दाएँ

1. कथा,गाथा-3
3. भगौना-3
5. पुष्पहार-2
6. वायदा,कसम-2
8. अभिष्ट इच्छापूर्ति,वर-4
11. योग्य,उपयुक्त-3
13. चिंतन,सोच-विचार-3
14. ताश का एक खेल-2
15. संजय दत्त की पहली फिल्म-2
16. चेहरा,शक्ल-3
18. चाकू,खंजर-3
20. उकसाना,चकमा देना -4
23. लक्ष,सौ हजार-2
25. ईश्वर,भगवान-2
26. विदा,गमन-3
27. लेखनी,पेन-3

ऊपर से नीचे

1. हुनर,फन-2
2. शांति,वीराना-3
3. चिलमन,ओट,घूंघट-3
4. ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ-2
5. माजरा,मुद्दा-3
7. आंगन,बरामदा-3
9. भागना (अंग्रेजी-2)
10. चटपटा,क्षारीय-4
12. कारनामा,करिश्मा-4
16. अच्छे सुर का ज्ञाता-3
17. मालिक,स्वामी-2
19. प्रेम प्रतिद्वंदी(उर्दू-3)
21. बेदखल करना-3
22. फिजूल,व्यर्थ-2
24. गधा,गर्दभ -2
25. एक प्रकार की विदेशी शराब-2

शब्द पहेली -8078 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

पेरिस ओलंपिक में नीरज, सिंधु के पास इतिहास रचने का अवसर,पदकों का आंकड़ा दो अंकों में पहुंचने की उम्मीदें

पेरिस (ईएमएस)। गुरुवार से यहां शुरु हो रहे पेरिस ओलंपिक में भी भारत के पास इस बार अपने पदकों का आंकड़ा दो अंकों में हासिल करने का अवसर है। भारत से 117 खिलाड़ियों का दल गया है और उसका लक्ष्य ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना रहेगा। इस बार भारतीय खिलाड़ियों का प्रयास एक से अधिक स्वर्ण जीतने का रहेगा। इसके अलावा इसमें नीरज चोपड़ा के पास दो स्वर्ण पदक लाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बनने का अवसर है। नीरज ने इससे पहले हुए टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। एक और जीत से वह दो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बन सकते हैं। वहीं बैडमिंटन में पी वी सिंधु पदक की हैट्रिक लगाने का प्रयास करेंगी।

ओलंपिक में भारत की ओर से महिला खिलाड़ियों ने अबतक कभी स्वर्ण पदक मेडल नहीं जीता है। ओलंपिक में महिलाओं ने 2 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। पेरिस में भारतीय महिला खिलाड़ियों के सामने इस उपलब्धि को हासिल करने का अच्छा अवसर रहेगा। भारत के अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग में पुरुष निशानेबाजी के व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं पेरिस में महिला निशानेबाजों सिफ्ट कौर सामरा और मनु भाकर के पास स्वर्ण जीतने का अवसर है। इसके अलावा निशानेबाजी में भारत के पास पहला मिश्रित टीम पदक लाने का भी मौका होगा। इसमें 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल दोनों इवेंट में भारतीय खिलाड़ी दावेदार हैं।

भारत ने अभी तक मुक्केबाजी में भी कोई स्वर्ण नहीं जीता है। पेरिस में निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन के पास ये उपलब्धि हासिल करने का अवसर है। लवलीना ने टोक्यो में कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ओलंपिक में पीवी सिंधु, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी, लक्ष्य सेन, एच एस प्रणय जैसे स्टार खिलाड़ी बैडमिंटन में स्वर्ण जीतने का प्रयास करेंगे। सिंधु के पास पदक की हैट्रिक लगाने का मौका है। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने रियो और टोक्यो ओलंपिक में रजत और कांस्य पदक जीते थे। ऐसे में वह लगातार तीन व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर पेरिस में इतिहास बना सकती हैं। इसके अलावा तीरंदाजी में भी भारत को पदक मिलने की उम्मीद है।

कोलंबिया में फुटबॉल मैदान पर हुए ड्रोन हमले में 10 लोगों की मौत

बोगोटा (ईएमएस)। दक्षिण-पश्चिम कोलंबिया के काउका विभाग में एक फुटबॉल मैदान पर ड्रोन हमले में एक नाबालिग सहित 10 लोगों की मौत हुई है। काउका में आर्मी सेसिफिक कमांड प्रमुख जनरल फेडेरिको मेजिया के अनुसार, यह हमला अर्जेलिया शहर के एल प्लेटेडो जिले में कोलंबिया विद्रोही समूह के निष्क्रिय हो चुके क्रांतिकारी सशस्त्र बलों के असंतुष्टों द्वारा किया गया।

उन्होंने कहा कि मैदान पर हमले से पहले, जहां बच्चे खेल रहे थे, विस्फोटकों से लैस ड्रोन द्वारा सेना पर 13 हमले हुए। उन्होंने कहा कि रात लगभग 9:00 बजे, फुटबॉल मैदान के पश्चिमी हिस्से में एक घर से भेजे गए आखिरी ड्रोन द्वारा मैदान पर एक विस्फोटक उपकरण गिराया गया, जिससे अज्ञात संख्या में लोग प्रभावित हुए और नाबालिग की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई।

10 अवैध प्रवासी की बाढ़ में डूबने से मौत

पनामा सिटी (ईएमएस)। लैटिन अमेरिका के पनामा में डेरियन गैप पैदल पार करते समय 10 अवैध प्रवासी नदी में अचानक आई बाढ़ में डूब गये। राष्ट्रीय सीमा सेवा ने इसकी जानकारी दी।

राष्ट्रीय सीमा सेवा के अनुसार, पीड़ितों के शवों को प्रवासी तस्करों से संबंध को छिपाने के लिए दफना करने के बाद सार्वजनिक मंत्रालय को घटना के बारे में जानकारी मिली। उल्लेखनीय है कि पूर्वी पनामा के डेरियन प्रांत का क्षेत्र दलदल जैसे जंगल और कीचड़ वाले रास्तों के कारण बेहद जोखिम भरा है। पनामा के अधिकारी प्रवासियों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित एक वैकल्पिक के मानवीय गलियारे के माध्यम से उन्हें बाहर निकालने कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ प्रवासी अधिक खतरनाक मार्ग चुनते हैं।

आम आदमी परेशान, पिछले दो माह में आलू-प्याज, टमाटर की कीमत 15 से 58 फीसदी तक बढ़ी

सरकार ने संसद में कहा... महंगाई अस्थाई, कीमतें जल्द होंगी नियंत्रित

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश में पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे है। आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। टमाटर, प्याज और आलू जैसी जरूरी सब्जियों की खुदरा कीमत पिछले एक महीने में 15 फीसदी से 58 फीसदी तक बढ़ गई हैं। सब्जियों के बढ़ते दामों के पीछे मानसून के अलावा कई अहम कारण जिम्मेदार माने जा रहे हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने दावा किया है कि यह स्थिति अस्थाई है। आने वाले दिनों में कीमतें जल्द ही नियंत्रण में आ जाएगी। लेकिन सब्जियों के दाम तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? इसके पीछे सरकार ने ये वजह बताई है।

पिछले दिनों संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में केंद्र सरकार ने सब्जियों के बढ़ती हुई कीमतों की वजह बताई है। सरकार ने बताया है कि पिछले दो वर्षों में खराब मौसम, जलाशयों का गिरते स्तर और फसल नुकसान ने कृषि उत्पादन को प्रभावित किया है। इसी वजह से तेजी से खाद्य कीमतों के दाम बढ़ रहे है। खराब मौसम की स्थिति ने सब्जियों और दालों के उत्पादन की संभावनाओं को प्रभावित किया है।

खराब मौसम के कारण फसलें खराब

रिपोर्ट में बताया गया है कि, देश में 2023-2024 में खराब मौसम की घटनाओं बहुत ज्यादा हुआ है। इससे फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। इसे अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में घटने जलाशय के स्तर ने भी कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसलिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 22 में 3.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 6.6 प्रतिशत और वित्त वर्ष 24 में 7.5 प्रतिशत हो गई। आर्थिक सर्वे में बताया गया कि, जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा क्षेत्र-विशिष्ट फसल पर रोग के कारण भी सब्जियों में सप्लाई में रुकावट आई है। इसी वजह से टमाटर में कीमतों में उछाल आया है। जबकि प्याज की कीमतों में उछाल के वजह पिछले कटाई सीजन में बारिश, बुवाई में देरी, लंबे समय तक सूखा और दूसरे देशों द्वारा व्यापार से जुड़े कदम उठाना है पिछले दो सालों में प्रतिकूल मौसम की वजह से कम उत्पादन की वजह से दालों, खास तौर पर अरहर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।

बाप रे बाप......दुनिया का सबसे गर्म दिन रहा रविवार का

वॉशिंगटन (ईएमएस)। गत रविवार को पृथ्वी का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ है, जो पिछले कुछ वर्षों में टूटे कई तापमान रिकॉर्ड में एक और इजाफा है। यह जानकारी यूरोपीय जलवायु सेवा कॉपरनिकस ने दी। रविवार 21 जुलाई को पिछले 100,000 वर्षों में सबसे गर्म दिन माना जा सकता है। कॉपरनिकस के अनुसार, साल 2024 बेहद गर्म रहा है, लेकिन रविवार को नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला मुख्य कारण सामान्य से अधिक गर्म अंटार्कटिक सर्दी थी। पिछले साल भी जब जुलाई की शुरुआत में रिकॉर्ड सेट हुआ था, तब भी दक्षिणी महाद्वीप में यही स्थिति थी। रविवार को केवल अंटार्कटिका ही नहीं गर्म था कैलिफ़ोर्निया के आंतरिक क्षेत्रों में भी तापमान तीन अंकों में पहुँच गया था, जिससे अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में दो दर्जन से अधिक आग की घटनाओं को और जटिल बना दिया।

वर्तमान में यूरोप भी अपनी खुद की घातक हीट वेव से जूझ रहा था। 2024 के पहले छह महीनों ने पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ते हुए, तापमान में और भी अधिक वृद्धि दर्ज की है। कोपरनिकस के अनुसार, 2024 के पहले छह माह में दर्ज हुआ तापमान पिछले वर्षों के रिकॉर्ड से भी अधिक गर्म था, जो एक नया चौंकाने वाला माप है। प्रारंभिक डेटा के अनुसार, रविवार को वैश्विक औसत तापमान 17.09 डिग्री सेल्सियस (62.76 डिग्री फारेनहाइट) था, जो पिछले साल 6 जुलाई, 2023 को स्थापित रिकॉर्ड को 0.01 डिग्री सेल्सियस (0.02 डिग्री फारेनहाइट) तोड़ता है। बता दें कि कॉपरनिकस एक प्रमुख यूरोपीय जलवायु सेवा है, जो जलवायु और मौसम संबंधी डेटा की निगरानी करती है। कॉपरनिकस का डेटा विश्वसनीय और वैज्ञानिक रूप से सटीक माना जाता है।

अनुमान है कि 2024 के 2023 को सबसे गर्म वर्ष के रूप में पार करने की 92 प्रतिशत संभावना है। पिछले 13 महीनों के तापमान में भारी वृद्धि ने इसे अपरिचित क्षेत्र में ला दिया है। सामान्य से अधिक गर्म अंटार्कटिक सर्दी ने रविवार के तापमान को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया।

अत्यधिक गर्मी के कारण ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक अत्यधिक गर्मी से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा फसलों पर नकारात्मक प्रभाव और जल संसाधनों की कमी हो सकती है।

रूस को यूक्रेन पर भरोसा नहीं, जेलेंस्की का बयान विश्वसनीय नहींः मारिया

मॉस्को (ईएमएस)। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा है कि रूस के साथ संभावित वार्ता पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान विश्वसनीय नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मारिया का यह बयान हाल ही में जेलेंस्की के उस बयान पर आया है जिसमें जेलेंस्की ने कहा था कि नवंबर में आयोजित होने वाले दूसरे शांति सम्मेलन में रूसी प्रतिनिधियों को मौजूद रहने का प्रस्ताव दिया था। मारिया ने कहा कि रूस को यूक्रेन के राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, उनके प्रशासन या उनके पश्चिमी क्यूरेटरों ने रूस के साथ बातचीत पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द करने की कोई कार्रवाई नहीं की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति और कीव के पश्चिमी सहयोगी एक बार फिर अपने असफल शांति फार्मूले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

मनाली में बादल फटने से आई बाढ़ में मकान व कई मवेशी बहे, पुलिस ने किया अलर्ट

मनाली (ईएमएस)। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बीती रात को बादल फटने से बाढ़ आ गई। भारी बारिश के चलते अंजनी महादेव नाले में सैलाब आ गया और बड़े-बड़े पत्थर बहकर नेशनल हाईवे पर आ गए जिससे हाईवे का यातायात बंद हो गया है वहीं लाहौल घाटी से आवाजाही हो रही है। पुलिस ने एडवायजरी जारी की है। फिलहाल मनाली में धूप खिली है और मौसम साफ है।

जानकारी के मुताबिक बीती रात मनाली में भारी बारिश हुई और फिर ब्यास नदी में मिलने वाले अंजनी महादेव नाले ने रौद्र रूप ले लिया। अटल टनल से पहले धुंधी में भी लैंडस्लाइड के चलते स्नो गैलरी में मलबा घुस गया। इसके अलावा यहां पर मनाली लेह हाईवे का एक हिस्सा ब्यास नदी में बह गया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि मनाली में बादल फटने से धुंधी से पलचान तक बाढ़ आ गई है। ऐसे में लोग इस मार्ग पर आने जाने से बचें।

अटल टनल के साउथ पोर्टल से आगे हाईवे बंद होने से केलांग मनाली-सरकाघाट बस नार्थ पोर्टल के पास रोक दी गई। सवारियों से खचाखच भरी बस को अब तक रोहतांग दर्रे से होकर जाने की अनुमति नहीं मिली है। लोगों ने विधायक अनुराधा राणा से आग्रह किया है कि केलांग डिपो प्रबंधन को वाया रोहतांग दर्रा बस चलाने का आदेश दिया जाए। फिलहाल अब तक कोई आदेश नहीं आया है।

जानकारी मिली है कि पलचान में दो मकान बाढ़ में बह गए हैं और एक को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा, पलचान से आगे पुल को भी नुकसान हुआ है। यहां बड़े-बड़े पत्थर आने से नाले ने अपना रुख बदल लिया और पुराने पुल की तरफ से यह बहने लगा। पलचान में 12 भेड़-बकरियां बाढ़ में बह गई हैं। अंजनी महादेव नाले ने पलचान पुल के पास अपना रुख मोड़ा था। उधर सोलंग नाला के समीप आखरी नाले में भी बाढ़ आने से सड़क को नुकसान पहुंचा है।

भारी बारिश और बाढ़ से पलचान, रुआड, कुलंग समेत नेहरुकुण्ड से पतलीकूहल तक के लोग प्रभावित हुए हैं। लोग रातभर सो नहीं पाए और आधी रात को अफरा तफरी का माहौल बना रहा। ब्यास नदी का पानी सड़क पर आ गया है। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है और लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

ब्राज़ील के टीवी कलाकार थॉमी की बालकनी से गिरने से मौत, फैंस हुए दुखी

लॉस एंजेलिस (ईएमएस)। आजकल फिल्मी जगत से बुरी खबर सुनने को मिल रही है। 18 जुलाई को एक्टर कृष्ण कुमार की बेटी का निधन हो गया था। वहीं अब एक और फिल्मी स्टार की मौत की खबर सामने आई है। ब्राजील के टीवी के मशहूर कलाकार थॉमी शियावो का 39 साल की उम्र में निधन हो गया। थॉमी के अचानक निधन से उनके फैंस हैरान हैं और यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि थॉमी अब इस दुनिया में नहीं रहे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर थॉमी शियावो का कुइआबा, माटो ग्रोसो, ब्राजील में अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहे थे और उसी दौरान वह अपने घर की बालकनी से नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई।

थॉमी की मौत की पुष्टि वहां की स्थानीय पुलिस ने की। रिपोर्ट के मुताबिक थॉमी अपने घर की दूसरी मंजिल की बालकनी पर बैठे थे और साथ अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद वह फर्श पर ही लेट गए। पुलिस ने जांच के बाद सीसीटीवी फुटेज में पाया कि थॉमी अपना बैलेंस खो बैठे थे और बालकनी से नीचे गिर गए। इस खबर से एक्टर के फैंस का दिल टूट गया है।

रुसी सेना में भर्ती हो जाओ,18 लाख रुपये का बोनस पाओ

मॉस्को (ईएमएस)। यूक्रेन जंग से रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दो साल से ज्यादा समय से चल रही जंग में दोनों ओर से कई सैनिक मारे गए हैं। इसके बाद सेना में सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए, रूसी अधिकारी नए सिपाहियों को रिकॉर्ड बोनस ऑफर कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने बयान जारी कर शहर के रहने वालों को सेना में भर्ती होने पर एक बार में 1.9 मिलियन रूबल (लगभग 18,41,697 रुपये) का बोनस देने की घोषणा की।

नए सिपाहियों को उनकी पहली साल की सेवा में 5.2 मिलियन रूबल (49,89,324.60 रुपये) तक का ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा, युद्ध में घायल होने वालों को उनकी चोटों की गंभीरता के आधार पर 4,76,329.82 रुपये से 9,53,496.77 रुपये तक का एकमुश्त भुगतान मिल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवारों को 28,58,816.03 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

रूस सरकार सैनिकों के मारने की संख्या छुपा रही है, लेकिन अनुमानों के मुताबिक सैनिकों की मौत की संख्या अधिक है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सिर्फ मई और जून में ही 70,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए या घायल हुए, क्योंकि रूस को खारकीव इलाके में भारी नुकसान हुआ। दिसंबर में कांग्रेस को दी गई अमेरिकी खुफिया जानकारी के मुताबिक रूस ने जंग शुरू होने से अब तक अपने सक्रिय जमीनी सैनिकों के 87 प्रतिशत और अपने टैंकों के दो-तिहाई हिस्से को खो दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है, सोशल मीडिया पर ड्रोन के वीडियो आ रहे हैं, इसमें रूसी सैनिक यूक्रेनी सेना के खिलाफ भयंकर लड़ाई में मारे जा रहे हैं या बुरी तरह घायल हो रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने बताया कि उन्हें रूसी सैनिकों के भारी हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें उनके कमांडर बेकार सामान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।

इन बढ़ती नुकसानों के चलते, रूस जल्दी से सैनिकों की संख्या बढ़ाना चाह रहा है। पुतिन ने सेना में 1,70,000 जवान भर्ती करने का आदेश दिया है, इसका मकसद सेना की संख्या 22 लाख से ज्यादा करना है, जिसमें 13.2 लाख सक्रिय सैनिक शामिल हैं। सेना के साइज में ये 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी है, और जंग शुरू होने के बाद से ये दूसरी बार है। रिपोर्टों के मुताबिक, रूस ने 15,000 नेपाली नागरिकों को भर्ती किया है, जिनमें से कई इस तरह के युद्ध से परेशान हैं, कुछ लापता हैं या संभवतः मारे गए हैं। इसके अलावा, अफगान, भारतीय, कांगोली और मिस्र के भर्तियों को रूस की सैन्य अकादमियों में ट्रेन किया जा रहा है।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

मुम्बई (ईएमएस)। घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट पर बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही धातु और बैंकिंग शेयरों में हुई बिकवाली से आई है। इसके अलावा प्रतिभूति लेनदेन कर और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी के कारण विदेशी कोषों की जमकर निकासी हुई जिससे भी बाजार नीचे आया। इंट्रा-डे कारोबार में भी गिरावट से बाजार पर दबाव पड़ा हालांकि टाटा मोटर्स और लार्सन एंड टुब्रो के शेयरों में तेजी से कुछ हद तक बाजार संभला। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 109.08 अंक या 0.14 फीसदी की गिरावट के साथ 80,039.80 पर बंद हुआ।

वहीं दूसरी ओर 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 7.40 अंक तकरीबन 0.03 फीसदी टूटकर 24,406.10 अंक पर बंद हुआ। आज के कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में 17 शेयर नुकसान के साथ ही नीचे आये। एक्सिस बैंक, नेस्ले इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन और टाटा स्टील सेंसेक्स के शीर्ष-5 नुकसान वाले शेयर रहे। इसके अलावा, इंडसइंड बैंक, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, एसबीआई, भारती एयरटेल, एचयूएल, टेक महिंद्रा, रिलायंस, इंफोसिस, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी और बजाज फिनसर्व के शेयर नुकसान में रहे।

वहीं दूसरी ओर सेंसेक्स के 13 शेयर लाभ पर बंद हुए। इसमें टाटा मोटर्स, एलएंडटी, सन फार्मा, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक सेंसेक्स के सबसे अधिक लाभ वाले पांच शेयर रहे। इसके अलावा, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, एचसीएल टेक, अदाणी पोर्ट्स, एमएंडएम, मारुति और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर लाभ के साथ ही ऊपर आये। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो एशियाई बाजारों में सियोल, टोक्यो, शंघाई और हांगकांग नीचे आये। इसके अलावा यूरोपीय बाजारों में भी गिरावट रही।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों गत दिवस बाजार में शुद्ध विक्रेता रहे। उन्होंने 5,130.90 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। वहीं गत कारोबारी दिन भी बाजार गिरावट पर बंद हुआ था।

इससे पहले आज सुबह बाजार की शुरुआत ?गिरावट के साथ हुई। बीएसई सेंसेक्स 600 अंक गिरकर 79,542 अंकों पर आ गया, जबकि निफ्टी50 इंडेक्स 183 अंक गिरकर 24,230 पर पहुंच गया।

ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदी नेजाद की हत्या की साजिश नाकाम!

तेहरान (ईएमएस)। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद पिछले हफ्ते एक हत्या की कोशिश से बाल-बाल बच गए, जब उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। यह जानकारी ईरान इंटरनेशनल के सूत्रों ने दी। जिसके मुताबिक उनकी गाड़ी में फिल्मी स्टाइल में गड़बड़ी की गई थी। जिससे वह बाल-बाल हादसे का शिकार हो जाए।

ईरान इंटरनेशनल के सूत्रों के अनुसार, करज-काज्विन राजमार्ग पर लगभग एक चौथाई रास्ते पर अहमदीनेजाद के सहयोगियों और अंगरक्षकों को ले जा रही टोयोटा लैंड क्रूजर के चालक ने अचानक स्टीयरिंग और ब्रेक दोनों पर नियंत्रण खो दिया। अनियंत्रित टोयोटा ने तेज गति वाले ट्रैफ़िक में तीन बार चक्कर लगाया, दो बार बाएं और दाएं मुड़ी, केंद्रीय बैरियर से टकराई और अहमदीनेजाद के काफ़िले में शामिल एक अन्य वाहन से टकराई। इसके बाद यह एक प्यूज़ो कार से टकराने के बाद फिर से बैरियर से टकराई। प्यूज़ो में सवार एक यात्री को चोटें आईं और उसे अस्पताल ले जाया गया। सौभाग्य से, चोटें मामूली थीं और व्यक्ति को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई।

चीन ने प्रमुख नीतिगत दर और बैंक जमा पर ब्याज घटाया

बैंकॉक (ईएमएस)। चीन ने प्रमुख नीतिगत दर और बैंक जमा पर ब्याज दर कम करके अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। यह कदम वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट को देखते हुए बढ़ाया गया है, जिससे चीनी बाजारों में नुकसान बढ़ गया है। बुधवार को दोपहर तक हांगकांग का हैंगसेंग 1.4 प्रतिशत तथा शंघाई कम्पोजिट सूचकांक 0.4 प्रतिशत नीचे आ गया। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने गुरुवार को कहा कि उसने एक साल के मध्यम अवधि के पॉलिसी लोन के लिए ऋण दर में 20 आधार अंकों की कटौती करके इसे 2.3 प्रतिशत कर दिया है। सात-दिन के ऋण पर ब्याज दर घटाकर 1.7 प्रतिशत कर दी गई है। प्रमुख सरकारी बैंकों ने अपने वित्त पर दबाव कम करने के लिए जमा दरों में कटौती की है। केंद्रीय बैंक ने इस सप्ताह की शुरुआत में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई अन्य ऋण दरों में कटौती की थी।

सेबी ने डीमैट एकाउंट के नियमों में किया बदलाव

मुंबई (ईएमएस)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट के नियमों में बदलाव किया है। बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट (बीएसडीए) के लिए सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की। यह नियम 1 सितंबर, 2024 से लागू होगा। सेबी ने हाल ही में बीएसडीए की पात्रता मानदंडों की व्यापक समीक्षा की, जिसका उद्देश्य शेयर बाजार में नए इंवेस्टर्स की हिस्सेदारी और निवेश को बढ़ावा देना है। यह सुविधा बाजार ?नियामक सेबी द्वारा 2012 में छोटे पोर्टफोलियो वाले निवेशकों पर डीमैट शुल्क के बोझ को कम करने के लिए शुरू की गई थी। बीएसडीए के लिए योग्यता पर सेबी ने कहा कि कोई व्यक्ति बीएसडीए के लिए योग्य है, बशर्ते वह कुछ मानदंडों को पूरा करता हो, जैसे कि निवेशक के पास एकमात्र या प्रथम धारक के तौर पर सिर्फ एक डीमैट खाता है, सभी डिपॉजिटरी में उसके नाम पर सिर्फ एक बीएसडीए है और खाते में सिक्योरिटीज की वैल्यू किसी भी समय डेट और नॉन-डेट सिक्योरिटीज दोनों के लिए संयुक्त रूप से 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। बीएसडीए के लिए पात्र होने के लिए आपका खाता केवल एक व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए आपके पास कोई अन्य डीमैट खाता नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बीएसडीए कैटेगिरी के अंतर्गत केवल एक ही डीमैट खाता रखा जा सकता है। यदि आपके पास संयुक्त खाता है, तो आप खाते के पहले धारक नहीं होंगे।

चीन के चांग'ई-5 ने चंद्रमा पर खोजा पानी, दशकों पहले लिए नमूनों में नहीं थे पानी के संकेत

बीजिंग (ईएमएस)। चीनी ने चंद्रमा की मिट्टी में पानी के अणुओं की एक अभूतपूर्व खोज की है। इसे एक ऐसी खोज माना जा रहा है, जो चंद्रमा के विकास के बारे में हमारी समझ को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है। यह खोज 2020 में चीन के चांग'ई-5 मिशन द्वारा वापस लाए गए चंद्र मिट्टी के नमूनों पर किए गए अध्ययनों पर आधारित थी। यह लंबे समय से चली आ रही इस धारणा को चुनौती देती है कि चंद्रमा पूरी तरह से सूखा है और पानी केवल बर्फ के रूप में मौजूद है। इसे अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि चीन ने चंद्रमा की मिट्टी को नासा के साथ साझा करने से इनकार किया है। यह वही नासा है, जिसने 2020 तक चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी से इनकार किया था।दशकों पहले, अमेरिकी अपोलो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के नमूने वापस लाए थे, जिनमें पानी के कोई संकेत नहीं थे। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि चंद्रमा की मिट्टी पूरी तरह से सूखी थी। इस निष्कर्ष का समर्थन नासा ने किया, जिसने दावा किया कि चंद्रमा की सतह पर पानी की कमी है। हालांकि, प्रौद्योगिकी में प्रगति और आगे के अन्वेषणों ने धीरे-धीरे इस धारणा को चुनौती देना शुरू कर दिया है।

चांग'ई-5 मिशन, जिसने 2020 में चंद्रमा के निकटवर्ती भाग से चंद्र नमूने प्राप्त किए, ने पानी की उपस्थिति की जांच करने का एक नया अवसर प्रदान किया है। ये नमूने पिछले अपोलो और सोवियत लूना मिशनों द्वारा एकत्र किए गए नमूनों की तुलना में कम उम्र के और उच्च अक्षांश से थे। बीजिंग नेशनल लेबोरेटरी फॉर कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स और इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स ऑफ द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस शोध को 16 जुलाई को नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित किया गया था। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा प्रदान किए गए नमूने का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने 1,000 से अधिक खनिज क्लैस्ट को अलग किया। इनमें एक प्लेट जैसा पारदर्शी क्रिस्टल था, जिसे अज्ञात चंद्र खनिज नाम दिया गया था, जिसमें पानी के अणु थे। टीम ने स्थानीय स्रोतों या रॉकेट निकास से संदूषण को खारिज कर दिया, यह सुझाव देते हुए कि पानी युक्त खनिज चंद्रमा पर उत्पन्न हुआ था।2009 में, भारत के चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान ने हाइड्रेटेड खनिजों के संकेतों का पता लगाया, जो चंद्रमा के सूर्य के प्रकाश वाले क्षेत्रों में पानी के अणुओं की उपस्थिति का संकेत देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन 2020 तक नासा ने इन्फ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के लिए स्ट्रेटोस्फेरिक वेधशाला से डेटा का उपयोग करके चंद्रमा की धूप की रोशनी वाली सतह पर पानी की खोज की घोषणा नहीं की थी। ये निष्कर्ष मुख्य रूप से रिमोट सेंसिंग और माइक्रोप्रोब जैसी तकनीकों पर आधारित थे, जिससे पता चला कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं के रूप में मौजूद हो सकता है।

अलास्का एयर डिफेंस जोन में रुस-चीन के विमान घुसे, अमेरिका ने रोका

वॉशिंगटन (ईएमएस)। उत्तरी अमेरिकी एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (एनओआरएडी) ने कहा कि उसने अलास्का तट के पास बमों से लैस चीन और रूस के दो लड़ाकू विमान देखे हैं। इन विमानों को रोकने के लिए फाइटर प्लेन भेजे हैं। उत्तरी अमेरिकी एयरोस्पेस डिफेंस कमांड ने कहा कि उसने दो रूसी टीयू-95 और दो चीनी एच-6 सैन्य विमान का पता लगाया है, जो अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में काम कर रहे थे।

एनओआरएडी ने कहा कि कनाडा और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने मिलकर चीन और रूस के चार विमानों को रोक दिया है। कमांड ने कहा कि इन विमानों ने अमेरिका या कनाडा के हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया लेकिन, अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में ही उड़ते रहे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमांड ने कहा कि चीन और रूसी विमानों की ओर से कोई संदिग्ध गतिविधियां देखने को नहीं मिली है। वह उत्तरी अमेरिका के पास निगरानी करना जारी रखेंगे। उत्तरी अमेरिकी एयरोस्पेस डिफेंस कमांड ने कहा कि वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में किसी भी अन्य विमान को अपनी पहचान देनी होती है। यह एक अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र है, जिसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सभी विमानों की पहचान की जरूरत होती है। इससे पहले कमांड ने मई में कहा था कि वह अलास्का एडीआईजेड में चल रहे चार रूसी सैन्य विमानों का पता लगा रही है। उस समय उन्होंने कहा था कि गतिविधि नियमित रूप से होती है और इसे खतरे के रूप में नहीं देखा जाता है।

निजी क्षेत्र को रोजगार के लिए सरकार के साथ काम करना चाहिएः आनंद महिंद्रा

नई दिल्ली (ईएमएस)। महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा कि भारत के निजी क्षेत्र को रोजगार सृजन तथा युवाओं को रोजगार योग्य बनाने की दिशा में सरकार के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास के अभाव में देश का जनसांख्यिकीय लाभांश, जनसांख्यिकीय आपदा में बदल सकता है। वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ-साथ वृद्धि के महत्व को पहचानती है। आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा ?कि जीडीपी में हमारी वृद्धि के मामले में हम दुनिया के लिए ईर्ष्या का विषय हैं। हमारे भविष्य को लेकर आश्वस्त होने के कारण हम निवेश के लिए दुनिया का पसंदीदा गंतव्य हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य यह सुनिश्चित करना है कि इस वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी तेजी आए। महिंद्रा ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित योजनाएं आशाजनक हैं। निजी क्षेत्र से भी अपनी भूमिका निभाने का आग्रह करते हुए महिंद्रा ने कहा कि उसे आगे आकर रोजगार तथा रोजगार योग्यता दोनों में निवेश करके अपनी भूमिका निभानी होगी।

अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत के कुछ क्षेत्रों की यात्रा करने से रोका

वॉशिंगटन (ईएमएस)। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत-पाकिस्तान सीमा और देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों की यात्रा न करने को कहा है। जहां नक्सलवादी सक्रिय हैं। विदेश विभाग ने कहा कि अपराध और आतंकवाद के कारण भारत में ज्यादा सावधानी बरतें। कुछ क्षेत्रों में जोखिम बढ़ गया है। अमेरिका ने भारत को लेवल 2 पर रखा है लेकिन कई हिस्सों को लेवल 4 में जिसमें जम्मू-कश्मीर, भारत-पाक सीमा, मणिपुर और मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्से हैं। इनकी यात्रा न करें। आतंकवादी बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकते हैं। वे पर्यटक स्थलों, परिवहन केंद्रों, बाज़ारों व शॉपिंग मॉल को निशाना बनाते हैं।

विदेश विभाग ने कहा कि हिंसा और अपराध के खतरे के कारण मणिपुर की यात्रा न करें। भारत में यात्रा करने वाले अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को मणिपुर जाने से पहले पूर्व अनुमति लेनी होगी। भारत सरकार विदेशी पर्यटकों को एलओसी के साथ कुछ क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं देती है। नक्सली भारत के एक बड़े क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो पूर्वी महाराष्ट्र और उत्तरी तेलंगाना से लेकर पश्चिमी पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। अमेरिकी सरकार के कर्मचारियों को महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की यात्रा करने के लिए भी अनुमति की जरुरी है। भारत में काम करने वाले अमेरिकियों को सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के साथ-साथ असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के बाहर किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले पूर्व अनुमति की लेनी होगी।

कमला हैरिस को जमकर मिला चंदा, फिर भी ट्रंप को हराने के लिए पैसों का पड़ेगा टोटा

वाशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस को जमकर चंदा मिल रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संभावना वास्तविकता बन जाए हैरिस समर्थकों ने डेमोक्रेटिक पार्टी को जमकर चंदा भेजना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट ने यह भी खुलासा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के दौड़ से हटने के बाद से डेमोक्रेट्स के लिए फंडिंग में एक बड़ा बदलाव देखा गया है। हैरिस के एक सलाहकार ने बताया कि पार्टी में कमला हैरिस के विरोधी भी उनके अभियान में योगदान देने के लिए अपनी जेबें खोल रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए धन उगाहने वाले प्लेटफॉर्म ने रविवार को बाइडन की घोषणा के बाद सिर्फ सात घंटों में लगभग 47 मिलियन डॉलर जुटाने की सूचना दी। एक स्थानीय अखबार ने खुलासा किया कि रविवार और सोमवार के दौरान, प्लेटफॉर्म ने सभी उम्मीदवारों और कारणों के लिए कुल मिलाकर लगभग 67 मिलियन डॉलर का दान दर्ज किया। हैरिस के अभियान ने रविवार और सोमवार शाम के बीच अपनी सभी धन उगाने वाली समितियों में 100 मिलियन डॉलर जुटाने की सूचना दी। जो मैनहट्टन व्यापार धोखाधड़ी मामले में मई में दोषी ठहराए जाने के बाद ट्रंप के अभियान द्वारा जुटाए गए 53 मिलियन डॉलर से ज्यादा है।

अगर अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी अगस्त में शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनती है, तो यह अमेरिकी लोकतंत्र के दो सदियों के इतिहास से अधिक समय में केवल दूसरी बार होगा, जब अमेरिकी मतदाता यह चुनाव कर सकेंगे कि वे अपना नेतृत्व करने के लिए किसी महिला को चुनेंगे या नहीं। उन्होंने केवल एक अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा को चुना है, मगर कभी किसी महिला को नहीं चुना है। अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनी जाती हैं, तो वे न केवल अमेरिकी राजनीति में सबसे कठिन परीक्षा को पार करेंगी, बल्कि वे पहली भारतीय अमेरिकी, पहली एशियाई, पहली अश्वेत महिला और जमैका मूल की पहली व्यक्ति भी बनेंगी, जो इस पद पर पहुंचेंगी। हैरिस के अभियान के अनुसार 11 मिलियन से ज्यादा दानदाताओं ने इसमें योगदान दिया, जिनमें से 62 फीसदी इस चुनाव चक्र में पहली बार दान करने वाले थे। एजेंसियों के पोल में पाया गया कि कमला हैरिस ने रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प पर मामूली दो प्रतिशत अंकों की बढ़त हासिल की है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ट्रम्प को 42 और हैरिस को 44 फीसदी समर्थन मिला है। रजिस्टर्ड मतदाताओं में से 56 फीसदी ने इस कथन पर सहमति जताई कि 59 वर्षीय हैरिस मानसिक रूप से तेज हैं और चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। जबकि 49 फीसदी ने 78 वर्षीय ट्रंप के बारे में यही कहा। बहरहाल इससे ट्रंप पर कोई असर नहीं पड़ा है, जो मानते हैं कि कमला हैरिस को हराना 'आसान होगा।'

वडोदरा में १४ इंच बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त

विश्वामित्री नदी उफान पर आई, मगर-मच्छों के शहर में घुसने का खतरा बढ़ा

वडोदरा, २५ जुलाई । वडोदरा में बुधवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश बुधवार सुबह तक रुक रुक जारी रही। इस तरह २४ घंटों में यहां १४ बारिश हो चुकी है। भारी बारिश के कारण शहर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं, विश्वामित्री नदी खतरे के निशान से ३ फीट ऊपर बह रही है। नदी में आई बाढ़ का पानी शहर में घुसने लगा है, जिससे शहर में मगरमच्छों के घुसने का खतरा बढ़ गया है। बता दें, विश्वामित्री नदी लगभग ४४१ मगरमच्छों की शरणस्थली है।

विश्वामित्री नदी का स्तर २९.१३ फीट तक पहुंच गया है, जबकि इसके खतरे का लेवल २६ फीट है। भारी बारिश के कारण वडोदरा में आज स्कूल-कॉलेज बंद रखे गए। कमाटी पुरा, परशुराम, भट्ठा समेत निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। विश्वामित्री नदी में बढ़ते जल स्तर के चलते एहतियातन कालाघोडा पुल से आवाजाही रोक दी गई है।

आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नं. जारी-वडोदरा कॉर्पोरेशन हेल्पलाइन- १८०० २३३ ०२६५ ,बाढ़ नियंत्रण - ०२६५ २४२५९२, एनडीआरएफ हेल्पलाइन- ९७११० ७७३७२,पशु हेल्पलाइन वी केयर- ९४०९०२७१६६

वडोदरा नगर निगम आयुक्त दिलीप राणा और कलेक्टर बिजल शाह भी गांधीनगर में आपातकालीन संचालन केंद्र से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में नगर निगम आयुक्तदिलीप राणा ने जानकारी दी कि वडोदरा शहर में एक दिन में १४ इंच बारिश के कारण कुल १४९३ लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है।

वडोदरा नगर निगम द्वारा कुल २० आश्रय स्थल बनाए गए हैं। ऊपरी इलाकों में बारिश की संभावना को देखते हुए एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की एक टीम को स्टैंड पर रखा गया है। लोगों को सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाने के लिए ३० बसें भी तैयार रखी गई हैं। एसीपी ने लोगों से अपील की है कि वे विश्वामित्री नदी के पास न जाएं।

वडोदरा ग्राम मामलतदार शैलेश देसाई ने कहा कि नदी में बढ़ते जल स्तर के कारण सुखलीपुर के ७१ और नदी के किनारे कोटाली के ७० लोगों सहित कुल १४१ लोगों को स्थानांतरित किया गया है। जिला प्रशासन ने आश्रय स्थलों में शरण लेने वाले लोगों के लिए भोजन और पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था की है। विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ने से कोटेश्वर गांव और कासा रेजीडेंसी का संपर्क टूट गया है। फिलहाल एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों से चल रहा है। एनडीआरएफ के जवान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं।

सीएमए नैन्टी शाह को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद के सचिव नियुक्त

सूरत । इंस्टीटयूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (सीएमए) के पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद ने मुंबई में हुई बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए नए पदाधिकारियों का निर्विरोध चुनाव किया है। इस चुनाव में

सूरत के सीएमए नैन्टी शाह को लगातार दूसरे साल सचिव पद की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएमए नैन्टी शाह को लगातार दूसरे साल मिली बड़ी जिम्मेदारी पूरे दक्षिण गुजरात सीएमए परिवार में खुशी का माहौल है।

छत्तीसगढ़ के सीएमए अरिंदम गोस्वामी को अध्यक्ष और बड़ौदा के सीएमए मिहिर व्यास को उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना गया है। सूरत के ही सीएमए चैतन्य मोहरीर को कोषाध्यक्ष पद मिला है।

सूरत के सीएमए नैन्टी शाह को लगातार दूसरे साल मिली इस बड़ी जिम्मेदारी से पूरे दक्षिण गुजरात में खुशी की लहर दौड़ गई है। सूरत दक्षिण गुजरात चैप्टर के अध्यक्ष कैलाश चंद्र गुप्ता और प्रबंध समिति ने नए पदाधिकारियों को बधाई दी है। चैप्टर ने कहा कि यह सूरत और दक्षिण गुजरात के लिए गर्व का क्षण है।

जलभराव कम होने के बाद सफाई अभियान तेज, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

सूरत२५ जुलाई । सूरत में लगातार बारिश के कारण शहर के विभिन्न इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। खासकर पिछले कुछ दिनों से निचले इलाकों में जलभराव की समस्या गंभीर थी। हालांकि, अब बारिश कम होने के साथ ही नगर निगम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से सफाई अभियान तेज कर दिया है।

शहर के विभिन्न जोनों में कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। महापौर दक्षेश मावानी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार काम कर रही हैं और सभी प्रभावित इलाकों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है।

शहर के निचले इलाकों में जलभराव कम होने और बारिश कम होने के साथ ही सफाई अभियान तेज कर दिया गया है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शहर के विभिन्न जोनों में कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है।स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार काम कर रही हैं और सभी प्रभावित इलाकों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है।

महापौर दक्षेश मावानी ने बताया कि शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

जैसे ही बारिश धमी, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई

सूरत शहर में पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ से शहरवासी बुरी तरह प्रभावित हुए थे। खाड़ियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न हो गए थे और लोगों को अपने घरों में कैद रहने को मजबूर होना पड़ा था।

हालांकि, मौसम में आए बदलाव के साथ बारिश थमने से स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। खाड़ियों में पानी का स्तर धीरे-धीरे कम होने लगा है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। बाढ़ के पानी से डूबे घरों और दुकानों को साफ-सफाई का काम शुरू हो गया है।

स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए हैं। लोगों को खाने-पीने का सामान और अन्य आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराई जा रही हैं। साथ ही, स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रही हैं।

सूरत के निवासियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्थिति और अधिक सामान्य हो जाएगी। हालांकि, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और भविष्य में आने वाली किसी भी आपदा के लिए तैयार रहने को कहा है।

मीठी और काकरा खाड़ी ओवरफ्लो होने से एक लाख लोग प्रभावित

सूरत में २४ घंटे में साढ़े ५ इंच बारिश हुई, मीठी खाड़ी ओवरफ्लो होने से आस-पास की सोसाइटियों, घरों और कपड़ा मार्केट में पानी भर गया, कपड़ा व्यापार ठप पड़ा

सूरत, २५ जुलाई । मीठी खाड़ी ओवरफ्लो होने से आस-पास की सोसाइटियों, घरों और कपड़ा मार्केट में पानी भर गया। इससे हजारों लोग प्रभावित हुए। शहर में बीते ७२ घंटे में १७ इंच और बीते २४ घंटे में साढ़े पांच इंच बारिश हुई है। गुरुवार को भी भारी बारिश की चेतावनी है।

मंगलवार-बुधवार की रात में ४ इंच बारिश हुई, जबकि बुधवार सुबह ६ बजे से रात १० बजे तक डेढ़ इंच बारिश हुई है। जिले में भारी बारिश से शहर की सीमाड़ा, मीठी, काकरा, भेदवाड और भाठेना खाड़ी में बाढ़ जैसी स्थिति है। कॉजवे का डैंजर लेवल ६ मीटर है, लेकिन यह ८.३१ मीटर पर पहुंच गया है। तापी नदी भी लबालब हो गई। पर्वत पाटिया और लिंबायत क्षेत्र में खाड़ी के आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। मीठी खाड़ी का जलस्तर ९ मीटर तक पहुंच गया है।

वराछा जोन-बी: आदर्श आश्रम शाला, राजीव नगर हरणपति, कठोदरा से १८२ लोगों को सरथाणा कॉम्युनिटी हॉल, वेलंजा स्कूल और अन्य जगह शिफ्ट किया। यहां ३१८५ फूड पैकेट बांटे गए।

लिंबायत जोन: हरणपतिवास, कमेला एरिया, प्लाजा नगर स्लम एरिया से १८० लोगों को मगोब विलेज के राजपूत भवन वाड़ी के रिलीफ सेंटर, ले कॉस्ट कॉलोनी, मान दरवाजा टेनामेंट में शिफ्ट किया। यहां ७८१५ फूड पैकेट बांटे गए।

उधना जोन ए: संजय नगर वसाहत से ३७ लोगों को भीमनगर प्राथमिक शाला में शिफ्ट किया गया। १००० फूट पैकेट बांटे गए।

उधना जोन-बी: संजय नगर-१ से २१३ लोगों को उनके रिश्तेदारों के घर पहुंचाया। १४०० फूड पैकेट बांटे गए। वराछा जोन-ए: हरणपति वास, सारोली गाम व वांसकोड़ा, सणिया ब्राह्मण फलिया, खाड़ी फलिया से १७५ लोगों को सारोली प्राथमिक शाला और उनके रिश्तेदारों के घर पहुंचाया। २००० फूड पैकेट बांटे गए। अठवा जोन: रसूलाबाद से १७० लोगों को भटार कॉम्युनिटी हॉल में शिफ्ट किया। ३००० फूड पैकेट बांटे।

शहर समेत जिले में पिछले ७२ घंटे से हो रही झमाझम बारिश से शहर का आधा हिस्सा खाड़ी बाढ़ से प्रभावित है। शहर का लिंबायत, वराछा, उधना और अठवा जोन से गुजरने वाली सारी खाड़ी उफान पर हैं। सीमाड़ा खाड़ी के ओवरफ्लो होने से सारोली रोड (सूरत-खटोदरा मेन रोड) पर ३ से ५ फीट तक पानी भर जाने से यातायात पूरी तरह ठप पड़ गया। यही नहीं मॉडल टाउन-२ और मॉडल टाउन-३ सोसायटी में भी ३ फीट पानी भर गया था। बारिश ने कपड़ा मार्केट ही नहीं आम जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है।

कई इलाकों के तालाब भी ओवरफ्लो हो गए हैं। भीमराड का तालाब ओवरफ्लो होने से पानी सड़क पर बह रहा है। इसमें मछलियां भी बाहर आ गई हैं। दूसरी तरफ स्कूलों में गुरुवार को अवकाश का निर्णय फिर स्कूल पर छोड़ दिया गया है। शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि स्कूल के प्रिंसिपल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति को देखकर छुट्टी का निर्णय ले सकते हैं।

हालांकि बुधवार को शहर और जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी रही। बारिश की स्थिति को देखते हुए गुरुवार को भी स्कूलों में पूर्ण रूप से छुट्टी घोषित की जा सकती थी। शहर में जगह-जगह पानी भरा हुआ है। इसे देखते हुए गुरुवार को स्कूल खुलने पर अभिभावकों और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भारी बारिश से कपड़ा व्यापार लगभग ठप पड़ गया है। सारोली में पानी भरने से यहां के अधिकतर मार्केट बंद रहे। १५० से अधिक ट्रांसपोर्टर की ट्रकें भी नहीं चलीं। इससे लगभग ५० करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। सीमाड़ा खाड़ी के खतरे के निशान से ऊपर बहने से बुधवार सुबह करीब ६ बजे से सारोली में कड़ोदरा-सूरत मुख्य मार्ग पर पानी भर गया। इस कारण सारोली के कपड़ा मार्केट तक आवाजाही बंद हो गई थी।

सीएमए नैन्टी शाह को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद के सचिव नियुक्त

सूरत । इंस्टीटयूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (सीएमए) के पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद ने मुंबई में हुई बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए नए पदाधिकारियों का निर्विरोध चुनाव किया है। इस चुनाव में सूरत के सीएमए नैन्टी शाह को लगातार दूसरे साल सचिव पद की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

छत्तीसगढ़ के सीएमए अरिंदम गोस्वामी को अध्यक्ष और बड़ौदा के सीएमए मिहिर व्यास को उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना गया है। सूरत के ही सीएमए चैतन्य मोहरीर को कोषाध्यक्ष पद मिला है।

सूरत के सीएमए नैन्टी शाह को लगातार दूसरे साल मिली इस बड़ी जिम्मेदारी से पूरे दक्षिण गुजरात में खुशी की लहर दौड़ गई है। सूरत दक्षिण गुजरात चैप्टर के अध्यक्ष कैलाश चंद्र गुप्ता और प्रबंध समिति ने नए पदाधिकारियों को बधाई दी है। चैप्टर ने कहा कि यह सूरत और दक्षिण गुजरात के लिए गर्व का क्षण है।

राज्य में मौसम का औसत 53 फीसदी बारिश, कच्छ जोन में सबसे अधिक 75 फीसदी वर्षा

वडोदरा । राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान आणंद जिले की बोरसद तहसील में सर्वाधिक 14 इंच बारिश हुई। इसके अलावा वडोदरा जिले की पादरा और वडोदरा तहसील के अलावा नर्मदा की तिलकवाडा तहसील में 8 इंच से अधिक, भरूच तहसील में 7 इंच से अधिक बारिश हुई। नवसारी की खेरगाम तहसील और छोटा उदेपुर की नसवाडी तहसील में 6 इंच से अधिक बारिश होने की जानकारी राज्य स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से मिली है।

स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 25 जुलाई सुबह 6 बजे तक पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम का औसत का कुल 53 फीसदी बारिश हो चुकी है। वहीं, कच्छ जोन में मौसम का सर्वाधिक 75 फीसदी बारिश हुई है। इसके बाद सौराष्ट्र जोन में 73 फीसदी बारिश हुई है। दक्षिण गुजरात में 63 फीसदी, पूर्व-मध्य गुजरात में 32 फीसदी, उत्तर गुजरात में सबसे कम 29 फीसदी बारिश हो चुकी है। इसके अलावा डांग की सुबीर तहसील, नर्मदा की नांदोद तहसील, वडोदरा की शिनोर तहसील, भरुच की अंकलेश्वर, झगडिया और हांसोट, गांधीनगर की देहगाम तहसील,

सूरत की महुवा तहसील में पिछले 24 घंटे के दौरान 5 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य की 15 तहसीलों में 4 इंच और 21 तहसीलों में 3 इंच बारिश हुई है। राज्य की करीब 25 तहसीलों में 2 इंच से अधिक और 47 तहसीलों में एक इंच बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे में आणंद जिले की बोरसद तहसील में 14 इंच बारिश, वडोदरा की पादरा व नर्मदा की तिलकवाडा तहसील में 8 इंच बारिश दर्ज की गई ।

गुरुवार को राज्य में सामान्य बारिश हुई है। सुबह 6 बजे से दिन के 12 बजे तक करीब 43 तहसीलों में बारिश हुई है। अन्य कुछ जगहों पर एक मिलीमीटर से भी कम बारिश हुई। इसमें सर्वाधिक बारिश दाहोद की लीमखेड़ा तहसील में सुबह 8 से 12 के बीच 32 मिलीमीटर (मिमी), वलसाड की कपराडा तहसील में 29 मिमी, धरमपुर में 22 मिमी, पंचमहाल की शेहरा तहसील में 21 मिमी, मोरवा हडफ में 20 मिमी, दाहोद की सिंगवड में 16 मिमी, नवसारी की खेरगाम में 16 मिमी, दाहोद की संजली में 15 मिमी, साबरकांठा के हिम्मतनगर में 10 मिमी और दाहोद शहर में 10 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

भारी बारिश से ढहा मकान, मां-बेटे की दर्दनाक मौत

अहमदाबाद, २५ जुलाई ।

मौसम विभाग ने भी प्रदेश की कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, साथ ही लोगों को जलाशयों और निचले इलाकों में न जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। साबरकांठा जिले में भी भारी बारिश और पूरे इलाके में जलभराव होने की वजह से लोग घरों के अंदर ही रहने को मजबूर हैं।

गुजरात के साबरकांठा जिले में भारी बारिश के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। भारी बारिश की वजह से कच्चे मकान की दीवार ढह जाने से मकान में सो रहे मां-बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक मां और उसका चार साल का बच्चा अपने कच्चे मकान में सो रहे थे। तभी रात में भारी बारिश की वजह से कच्चे मकान की दीवार उनके ऊ पर गिर गई। जिससे दोनों दीवार के मलबे में दब गए।

घटना की जानकारी होते ही स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में दोनों को पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने मां को मृत घोषित कर दिया।

राज्य में बारिश की स्थिति के लिए "शून्य हताहत" दृष्टिकोण के साथ

भरूच, २५ जुलाई ।

राज्य में भारी बारिश की स्थिति से निपटने के लिए राज्य और जिला प्रशासन द्वारा शून्य हताहत दृष्टिकोण के साथ युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल के मार्गदर्शन में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा निरंतर निगरानी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा राहत अभियान चलाया जा रहा है।

एनडीआरएफ की टीम ने आज पोरबंदर जिले के चिंगरिया और मंडेर गांवों के निचले इलाकों में फंसे 6 लोगों को बचाया। एनडीआरएफ की टीम ने 2 बच्चों, एक पुरुष और एक महिला सहित कुल 6 लोगों को बचाया और छोटे बच्चे की मेडिकल इमरजेंसी होने पर उन्हें सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया।

इसी तरह, वडोदरा शहर के वडसर इलाके में बाढ़ के कारण फंसे 49 लोगों को एनडीए आरएफ टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इनमें 19 पुरुष, 15 महिलाएं, 14 बच्चे और एक छोटा बच्चा शामिल है।

अजवा झील से पानी छोड़े जाने के कारण विश्वामित्री नदी के किनारे बसे सुखालीपुरा, कोटाली, देना और असोज गांव में बढ़ते जल स्तर के कारण सुखालीपुरा के 71 और कोटाली के 70 सहित कुल 141 लोगों को आश्रयों में स्थानांतरित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने आश्रय स्थलों में शरण लेने वाले लोगों के लिए भोजन और पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था की है।

भरूच जिले में जम्बूसर के इंदिरा नगर, बंबूसर, करगट, परीज, जांगर और सामोद आदि स्थानों के प्रवासी आश्रितों के लिए उत्कृष्ट भोजन और आवास सुविधाएं बनाई गईं। भरूच जिले में मूसलाधार बारिश और वर्षा जल बाढ़ के कारण विस्थापित आश्रितों को जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां प्रभावित आश्रितों को भोजन, पीने का पानी, आवश्यक दवा, शयन चटाई, चादर सहित आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

दक्षिण गुजरात में भारी बारिश से निचले इलाकों में लोग प्रभावित हुए हैं. सूरत के ऑलपाड तालुक के वडोली गांव में भारी बारिश के बाद निचले इलाके में पानी भर जाने से 4 लोग फंस गए. स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने फंसे हुए 4 लोगों और जानवरों को बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

26 जुलाई को अहमदाबाद-पटना के बीच वन-वे स्पेशल ट्रेन

अहमदाबाद, 24 जुलाई

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद और पटना के बीच 26 जुलाई 2024 को वन वे स्पेशल ट्रेन विशेष किराये पर चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 09413 अहमदाबाद-पटना स्पेशल 26 जुलाई 2024 शुक्रवार को अहमदाबाद से 16.35 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन रविवार को 07.00 बजे पटना पहुंचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन नडियाद, आणंद, छायापुरी, गोधरा, रतलाम, भवानी मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, आगरा फोर्ट, टूंडला, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, अयोध्या कैंट, अकबरपुर, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर एवं आरा स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में 20 कोच स्लीपर श्रेणी एवं एक कोच सामान्य श्रेणी का रहेगा।

बच्चों को तेजी से अपनी जकड में ले रहा ये खतरनाक वायरस

अहमदाबाद, २५ जुलाई ।

गुजरात में बुधवार को भी इसके कारण तीन बच्चों को जान गंवानी पड़ी। इसके साथ ही इस वायरस के कारण अब तक ४१ बच्चों की मौत हो चुकी है।देश के कई हिस्सों में चांदीपुरा वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गुजरात में बुधवार को भी इसके कारण तीन बच्चों को जान गंवानी पड़ी। इसके साथ ही इस वायरस के कारण अब तक ४१ बच्चों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में चांदीपुरा वायरस के संदिग्ध और पॉजिटिव समेत ११८ मामले हो गए हैं। इनमें सबसे अधिक १५ मामले पंचमहाल जिले में हैं।

नेट का उपयोग करें: मच्छरों को कीड़ों से बचने के लिए रात में नेट का उपयोग करना चाहिए। मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें: मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करके मच्छरों को दूर रखा जा सकता है। खिड़की और दरवाजों को बंद रखें: घर के अंदर मच्छरों को आने से रोकने के लिए खिड़की और दरवाजों को बंद रखना चाहिए।

क्या है और कैसे फैलता है - डॉक्टर की सलाह लें: अगर आपको चांदीपुरा वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।

चांदीपुरा वायरस क्या है: यह एक आरएनए वायरस है जो मादा फ्लेबोटोमाइन मक्खी से फैलता है। चांदीपुरा वायरस के लक्षण: बुखार, फ्लू जैसे लक्षण, तेज एन्सेफलाइटिस (दिमाग में सूजन)। चांदीपुरा वायरस कितना खतरनाक है: यह वायरस शिशुओं और वयस्कों दोनों के लिए घातक हो सकता है। वायरस से संक्रमित बच्चे लक्षण दिखने के ४८-७२ घंटों के भीतर मर जाते हैं।

चांदीपुरा वायरस से बचाव के उपाय - मच्छरों से बचने के लिए रात में और सुबह-शाम फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना चाहिए। मच्छरों को कीड़ों से बचने के लिए रात में नेट का उपयोग करना चाहिए। मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करके मच्छरों को दूर रखा जा सकता है। घर के अंदर मच्छरों को आने से रोकने के लिए खिड़की और दरवाजों को बंद रखना चाहिए। अगर आपको चांदीपुरा वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।

कांग्रेस की 'हाथ से हाथ' यात्रा शुरू

वडगाम, 25 जुलाई

चूंकि स्थानीय स्वराज चुनाव नजदीक हैं, कांग्रेस पूरे गुजरात में सक्रिय रूप से चुनाव कार्य में लगी हुई है। आज दिनांक 25/7/24/ को सुबह 11 बजे बनासकांठा जिले के वडगाम में ठहाथ थी हाथ जोड़ोठ समिति के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रनीलभाई राजगुरु की अध्यक्षता में त्रिगुणात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें न्याय यात्रा का रथ पूरे जिले में घूमेगा। जिसे जिला कांग्रेस अध्यक्ष और हैंड-टू-हैंड जोड़ो कमेटी के पदाधिकारियों ने हरी झंडी दे दी.

पश्चिमी रेलवे चलायेगी अहमदाबाद से कुडाल और मंगलुरु के बीच गणपति स्पेशल ट्रेनें

पश्चिम रेलवे गणपति महोत्सव 2024 के दौरान अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से और अहमदाबाद-मंगलुरु स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः

1. ट्रेन संख्या 09412 अहमदाबाद-कुडाल साप्ताहिक स्पेशल 03, 10 और 17 सितंबर, 2024 (मंगलवार) को अहमदाबाद से 09.30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 03.30 बजे कुडाल पहुँचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09411 कुडाल-अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल 04,11 और 18 सितंबर 2024 (बुधवार) को कुडाल से 04.30 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 23.45 बजे अहमदाबाद पहुँचेगी।

यह ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में वडोदरा, सूरत, वापी, पालघर, वसई रोड,पनवेल,रोहा,मानगांव,वीर, करंजाडी, खेड़, चिपलून, सावर्डा, आरवली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, आडवली, विलवडे, राजा पुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नांदगांव रोड, कणकवली और सिंधुदुर्ग स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09424 अहमदाबाद- मंगलुरु साप्ताहिक स्पेश ल 06,13 और 20 सितंबर, 20 24 शुक्रवारकोअहमदाबादसे 16.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 19.45 बजे मंगलुरु पहुँचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09423 मंगलुरु-अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल 07,14 और 21 सितंबर, 2024 शनिवार को मंगलुरु से 22.10 बजे प्रस्थान करेगी और सोमवार को 02.15 बजे अहमदाबाद पहुँचेगी।

यह ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में नडियाद,आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, वसई रोड, पनवेल, रोहा, मानगांव, खेड़, चिपलून, सावर्डा, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाड़ी रोड, थिविम, करमाली, मडगांव, काणकोण, कारवार, अंकोला, गोकर्ण रोड, कुमटा, मुर्डेश्वर, भटकल, मूकाम्बिका रोड बैंदूर, कुंन्ढापुरा, उडुपि, मुल्की और सुरतकल स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे होंगे।

ट्रेन संख्या 09412 और 09424 की बुकिंग 28 जुलाई, 2024 से सभी पीआरएस काउंटरों और ध्ंऊ वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया **www. enquiry .indian rail.gov.in** पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे - वडोदरा मंडल

शुद्धिपत्र

ई-निविदा सं. **CPM-GSENGG-BRC-02-24-25 का शुद्धिपत्र** वेबसाईट www.ireps.gov.in पर अपलोड किये गइ उपरोक्त ई-निविदा के विवरण में निम्न निर्दिष्ट संशोधन कीये गये है : **अनु. सं. (i) विवरण :** प्रशासनिक कारणों की वजह से निविदा बंद होने के दिनांक को 07.08.2024 से 28.08.2024 तक विलंबित किया गया है । **निविदा के अन्य विवरण अपरिवर्तनिय रहेंगे।**

BRC-131

हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे - वडोदरा मंडल

वर्तमानित OHE में संशोधन

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए मंडल रेल प्रबंधक (विद्युत कर्षण), पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-390 004 द्वारा निम्नानुसार कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। **क्रम सं.1 : निविदा सं. EL/TRD/Tender/23-24/22R4. कार्य का नाम:** वडोदरा मंडल के सुरत - गेरतपुर, वडोदरा- गोधरा और वडोदरा-डभोई अनुभाग में रोड अंडर ब्रिज (RUB) के प्रावधान और पोर्टल/TTC के ड्रॉप आर्म (DA/Boom) पर नंबर प्लेट्स के प्रावधान की वजह से वर्तमान के OHE में संशोधन करने का कार्य । **कार्य की अनुमानित लागत (रु.में): ₹ 1,26,31,886/- बिड सिक्युरीटी (रु.में): ₹ 2,13,200/- निविदा दस्तावेज की लागत एवं समापन अवधि:** समापन अवधि 12 माह, **निविदा समय सारणी :** निविदा बंद होने की दिनांक 22/08/2024 एवं बंद होने का समय उसी दिनांक को 15:00 बजे । **वेब पेज विवरण एवं नोटीस स्थान जहाँ संपूर्ण विवरण देखा जा सकेगा तथा कार्यालय और स्पष्टीकरण का पता: वेबसाईट: @ www. ireps.gov.in** मंडल रेल प्रबंधक (विद्युत कर्षण), पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-390 004.

BRC-132

हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

गुजरात में भारी बारिश से आठ की मौत, कई नदियां उफान पर

अहमदाबाद, २५ जुलाई ।

गुजरात में भारी वर्षा के चलते हुईं विभिन्न घटनाओं में लगभग आठ लोगों की मौत हो गई। भारी वर्षा के चलते राज्य के बड़े हिस्से में नदियों और बांधों के उफनने से कई गांवों में पानी भर गया है। विभिन्न गांवों में फंसे आठ सौ से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य के सभी २०६ प्रमुख बांध भर गए हैं।

गुजरात में भारी वर्षा के चलते हुईं विभिन्न घटनाओं में लगभग आठ लोगों की मौत हो गई। भारी वर्षा के चलते राज्य के बड़े हिस्से में नदियों और बांधों के उफनने से कई गांवों में पानी भर गया है। विभिन्न गांवों में फंसे आठ सौ से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक अधिकारी के अनुसार, वडोदरा, सूरत, भरूच और आणंद जैसे जिलों में बुधवार सुबह से भारी वर्षा होने से सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कुछ स्थानों पर स्कूलों और कालेजों में दिनभर की छुट्टी घोषित करनी पड़ी। कुछ इलाकों में ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुईं।

राहत आयुक्तआलोक कुमार पांडे ने कहा कि पिछले २४ घंटों के दौरान गुजरात के कई हिस्सों में हुई भारी वर्षा के कारण आठ लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान ८२६ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की २० टीमों को तैनात किया गया है।

उन्होंने कहा कि मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) द्वारा कई जिलों के लिए जारी भारी वर्षा के रेड अलर्ट के मद्देनजर स्थिति पर नजर रखने और फंसे हुए लोगों की मदद के लिए नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी २०६ प्रमुख बांध भर गए हैं। राज्य का सबसे बड़ा सरदार सरोवर बांध अब ५४ प्रतिशत भर चुका है। आनंद जिले के बोरसाद तालुका में १२ घंटे के दौरान ३५४ मिमी वर्षा हुई। अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार को सूरत में हुई भारी वर्षा से शहर में बाढ़ आ गई। कई गांवों का संपर्क टूट गया। लगभग २०० लोगों को दूसरे स्थानों पर ले जाया गया।

मुख्यमंत्री ने वर्षा प्रभावित जिलों के कलेक्टरों-आयुक्तों से ली जानकारी

गांधीनगर, 25 जुलाई (हि.स.)। राज्य में भारी वर्षा से उत्पन्न हुई स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुरुवार को गांधीनगर स्थित स्टेट इमर्जेंसी ऑपेशन सेंटर (एसईओसी) पहुंचे। यहां पटेल ने भारी वर्षा से प्रभावित सात जिलों के कलेक्टरों तथा वडोदरा व सूरत महानगर पालिकाओं के आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की और स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर मुख्य सचिव राजकुमार एवं वरिष्ठ सचिव रैंक के अधिकारी भी मौजूद थे।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा आश्रय स्थानों में स्वास्थ्य, खाद्यान्न आपूर्ति आदि की सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने निर्देश दिया कि जलभराव वाले क्षेत्रों में वर्षा रुकने और पानी उतरते ही तत्काल मिट्टी-कीचड़ की सफाई के कार्य, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने के कार्य और धराशाई पेड़ों का मलबा हटाने के कार्य प्राथमिकता के साथ शुरू किए जाएं। पटेल ने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों की सतर्कता तथा समन्वय के फलस्वरूप हम व्यापक नुकसान रोक सके हैं। उन्होंने आगामी समय में वर्षा ऋतु के दौरान यदि और अधिक वर्षा हो, तो भी इसी सतर्कता के साथ कार्य रहने के लिए मार्गदर्शन दिया। उन्होंने स्टेट कंट्रोल रूम के साथ निरंतर सम्पर्क में रह कर कम से कम नुकसान हो; ऐसे अग्रिम आयोजन के लिए भी आवश्यक सुझाव दिए।

मुख्यमंत्री ने वर्षा से विद्युत आपूर्ति प्रभावित कई क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य करने व विद्युत आपूर्ति बहाल करने की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सड़क एवं भवन विभाग को सड़कों-मार्गों को हुए नुकसान की मरम्मत करने, बंद सड़कों पर पुनः यातायात बहाल करने के निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित विभागों से कहा कि जरूरत पड़े तो निकटस्थ जिलों से संसाधनों एवं मैनपावर की व्यवस्था करके भी स्थिति को तेजी से पूर्ववत किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में जो जलाशय, बांध पूरी तरह भर गए हैं या खतरे के निशान पर हैं, उन क्षेत्रों में वर्षा, बांध-जलाशय के ऊपरी क्षेत्र में वर्षा की लगातार मॉनिटरिंग करने और कमांड व कैचमेंट क्षेत्र के लोगों के जान-माल की सुरक्षा की दिशा में कदम उठाए जाएं।

मालिक, मुद्रक-प्रकाशक व सम्पादक : लक्ष्मीचन्द जी. अग्रवाल द्वारा ब्रिजाशा ऑफसेट, सरसपुर, अहमदाबाद में मुद्रित करवाकर, स्वेतप्रित बिल्डिंग, खासवाड़ी, बहुचराजी रोड़, वड़ोदरा से प्रकाशित किया। प्रातःकालीन E-mail: janhitaishi@yahoo.co.in Mob.9375504122 R.N.I. 64278/96